सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 234, नई दिल्ली । रविवार, 03 नवम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

यह मत मानिए कि जीत ही सब कुछ है, महत्वपूर्ण यह है कि आप किस उद्देश्य के लिए जीतना चाहते हैं...

03 दिल्ली में छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

06 पाठ्यक्रम में जुड़ने से युवाओं को लाभ

08 भारतीय नदी परिषद अध्यक्ष रमन कांत ने बताईं यमुना की 3 समस्याएं

दिल्ली परिवहन विभाग जल्द ही राजा गार्डन क्षेत्रीय कार्यालय को ताला लगवाकर यहां के कार्य को द्वारका क्षेत्रीय कार्यालय में कर देगा विलय

संजय बाटला

नई दिल्ली। विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली परिवहन आयुक्त सरकारी खर्चों को कम करने के उद्देश्य से हठ पूर्वक राजा गार्डन क्षेत्रीय कार्यालय पर ताला लगवाने का मन बना चुके हैं और बिना किसी पूर्व सूचना के कभी भी ताला लगवाने के आदेश जारी कर सकते है।

आपकी जानकारी हेतु याद करवा दें की जनकपुरी क्षेत्रीय कार्यालय में काम की अधिकता को देखते हुए दिल्ली की जनता के लिए जनकपूरी क्षेत्रीय कार्यालय से कुछ क्षेत्रों को काट कर गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा जनहित में राजा गार्डन कार्यालय खोला गया था।

दूसरी महत्वपूर्ण बात याद करने योग्य है की पहले परिवहन आयुक्त ने जनकपुरी क्षेत्रीय कार्यालय में ताला लगा कर उसके कार्य को राजा गार्डन क्षेत्रीय कार्यालय में विलय किया था।

द्वारका क्षेत्रीय कार्यालय में पहले से ही एक क्षेत्रीय कार्यालय का विलय किया हुआ है और अब जनकपुरी क्षेत्रीय कार्यालय एवम् राजा गार्डन क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यों को भी द्वारका क्षेत्रीय कार्यालय में विलय करने के आदेश जल्द जनता के समक्ष होगे।

दिल्ली में अधिकृत रूप 13 क्षेत्रीय कार्यालय आज भी कार्य कर रहे हैं पर यथा स्थिति जनता के लिए वह 13 नहीं सिर्फ 4 ही है। अर्थात सरकारी कागजों के अनुसार, गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार एवम् लेखा जोखा के अनुसार 13 क्षेत्रीय कार्यालय आज भी जनहित में कार्य कर रहे हैं*

आपकी जानकारी हेतु बता दे इन कार्यालयों को बन्द करने का उद्देश्य मात्र सरकारी खर्चों में कटौती नहीं है इसके पीछे का कारण इन क्षेत्रीय कार्यालयों की बेशकीमती जमीन बड़ी कंपनियों को सौंपना भी है। कुल मिलाकर जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जगह राजस्व और सिर्फ राजस्व कमाना ही आज परिवहन आयुक्त का उद्देश्य है. क्या जनहित के सरकारी कार्यालय के आला अधिकारी का कर्तव्य जनता को सुविधाएं उपलब्ध करवाना होता है या प्राप्त सुविधाओं को छीन कर राजस्व वसूली, सवाल बड़ा है पर कोई जवाब नहीं देगा क्योंकि आज जनहित में नहीं सिर्फ राजस्व की होड़/दौड़ में शमिल है प्रशासन और सरकार (चाहे किसी भी दल की हो)।

सड़क सुरक्षा में श्रीकृष्ण का संदेश : अंकुर शरण

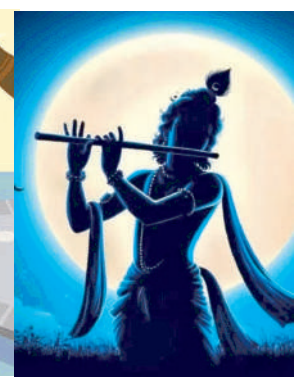

परिवहन विशेष न्यूज

महाभारत में एक प्रमुख क्षण है जब श्रीकृष्ण ने अर्जुन को युद्धभूमि में समझाया कि जब तक तुम स्वयं अधर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यह वाक्य हम सभी ने सुना है और इसकी गहराई को समझा भी है। आज जब हम अपने आसपास सड़क दुर्घटनाओं को देखते हैं, तब यही सीख हमें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और सतर्क रहने की प्रेरणा देती है।

हमारे समाज, मोहल्ले, और आसपास के क्षेत्रों में कई ऐसे काम होते हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज़ करते रहते हैं, और जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं हो जाता, हमें उनकी गंभीरता का आभास नहीं होता। ऐसे समय में, श्रीकृष्ण का वही संदेश हमें याद आता है—कि हमें स्वयंसेवक बनकर सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा और इसके प्रति जिम्मेदारी लेनी होगी।

सड़क सुरक्षा का महत्व सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है। समाज में हर व्यक्ति का दायित्व है कि वह न सिर्फ अपने लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी सुरक्षित माहौल बनाए। सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को यह समझना होगा कि दुर्घटनाएं केवल नियमों की अनदेखी के कारण नहीं होतीं, बल्कि यह हमारे उस लापरवाह रवैये का परिणाम है जो हमें अपने ही आसपास फैली समस्याओं से विमुख कर देता है।

आज ज़रूरत है कि हम सभी मिलकर एक ठोस कदम उठाएं। हमें अपने मोहल्ले, समाज, और सार्वजनिक स्थानों पर सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता फैलानी होगी। इसके लिए स्वयंसेवकों की टीम तैयार करें जो लोगों को सड़क नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करे, साथ ही बच्चों और युवाओं को भी सुरक्षा के नियमों से अवगत कराएं।

श्रीकृष्ण का यह संदेश हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत बन सकता है। आइए, हम सब मिलकर सड़क सुरक्षा को एक आंदोलन के रूप में अपनाएं, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक सुरक्षित और जागरूक समाज का निर्माण कर सकें।

नमो भारत ट्रेन के यात्रियों के लिए अच्छी खबर रविवार को 2 घंटे पहले शुरू होगी ट्रेन सेवा

परिवहन विशेष न्यूज

रविवार को भाई दूज के अवसर पर नमो भारत ट्रेन सुबह 6 बजे से शुरू होगी। आम तौर पर यह ट्रेन रविवार को सुबह 8 बजे से चलती है। यात्रियों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था की गई है। इस दिन ट्रेनों का परिचालन अधिक संख्या में किया जाएगा। बता दें नमो भारत का परिचालन सोमवार से शनिवार तक सुबह छह बजे से शुरू होती है।

नई दिल्ली। नमो भारत ट्रेन भाई दूज के अवसर पर रविवार को सुबह छह बजे से शुरू होगी। एनसीआरटीसी ने कहा कि नमो भारत का परिचालन रविवार को अपनी सामान्य टाइमिंग से दो घंटे पहले शुरू होगी। बयान के अनुसार, दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के परिचालन खंड पर ट्रेन सेवाएं रविवार को जल्दी शुरू होंगी, जो सामान्य सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 6 बजे से संचालित होंगी।

बयान में कहा गया कि नमो भारत का परिचालन रात 10 बजे तक जारी रहेगा। इसमें कहा गया है कि आम तौर पर नमो भारत ट्रेन सेवाएं सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 बजे और रविवार को सुबह 8 बजे से संचालित होती हैं। बयान में कहा गया है कि यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। इसके साथ इस दिन ट्रेनों का परिचालन अधिक संख्या में किया जाएगा।

दिल्ली के न्यू अशोक तक शुरू होगा परिचालन

बता दें, जल्द ही साहिबाबाद से दिल्ली के न्यू अशोक नगर के बीच इसका ट्रायल रन शुरू किया। अगले वर्ष जून तक 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर इस ट्रेन का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। इससे एक घंटे से भी कम समय में दिल्ली से मेरठ की यात्रा संभव हो सकेगी। फिलहाल नमो भारत ट्रेन रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के साहिबाबाद स्टेशन से मेरठ साउथ तक 42 किलोमीटर के खंड में संचालित है। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक नमो भारत ट्रेन चलने से आरआरटीएस के संचालित खंड की लंबाई बढ़कर 54 किलोमीटर हो जाएगी, जिसमें 11 स्टेशन होंगे।

नमो ट्रेन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर इस खंड की लंबाईः लगभग 12 किमी

आनंद विहार और न्यू अशोक नगर दो आरआरटीएस स्टेशन हैं।

आनंद विहार आरआरटीएस स्टेशन सबसे ज्यादा भीड़ वाला स्टेशन होगा। इस स्टेशन से दो मेट्रो लाइनों (ब्लू और पिंक), आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दिल्ली व कौशांबी (उत्तर प्रदेश) दो आईएसबीटी जुड़ेंगे। इसे मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन के मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है।

न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन 100 मीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। दोनों को फुटओवर ब्रिज (एफओबी) से जोड़ा जाएगा। आरआरटीएस स्टेशन पर पहुंचने के लिए चिल्ला गांव व मयूर विहार एक्सटेंशन की ओर से और प्राचीन शिव मंदिर के पास से दो एफओबी होंगे।

बदरपुर-आश्रम लेन पर जल्द शुरू होगा काम, दिल्ली-NCR के लोगों को करना होगा जाम का सामना

सरिता विहार फ्लाईओवर के एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम पूरा हो गया है। अब पीडब्ल्यूडी बदरपुर-आश्रम लेन पर काम शुरू करेगा। प्रदूषण के चलते तीसरे और चौथे चरण का काम शुरू करने पर फैसला नहीं हो पाया है। यातायात विभाग के मुताबिक अगले हफ्ते से काम शुरू हो सकता है। काम शुरू होने के बाद नोएडा से फरीदाबाद और फरीदाबाद से नोएडा आने-जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है।

दक्षिणी दिल्ली। सरिता विहार फ्लाईओवर पर आश्रम-बदरपुर लेन पर एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलने का काम पूरा हो चुका है। पीडब्ल्यूडी अब जल्द ही बदरपुर-आश्रम लेन पर काम शुरू करेगा। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़े स्तर को देखते हुए फिलहाल तीसरे व चौथे चरण का काम शुरू करने को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है।

यातायात विभाग के मुताबिक काम अगले सप्ताह से शुरू किया जा सकता है। सरिता विहार फ्लाईओवर के दोनों लेन पर पीडब्ल्यूडी को एक्सपेंशन ज्वाइंट बदलना है। काम चार चरणों में होना है। पहले 15-15 दिन के दो चरणों में मरम्मत का काम आश्रम से बदरपुर जाने वाली लेन पर तीन अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसे पूरा कर लिया गया है।

अगले सप्ताह काम हो सकता है शुरू-ट्रैफिक पुलिस

एक नवंबर से तीसरे चरण का काम बदरपुर-आश्रम लेन (Badarpur-Ashram Lane) पर शुरू होने था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने के चलते शुक्रवार को तीसरे चरण का काम शुरू नहीं हो पाया। हालांकि इसे लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। यातायात विभाग के मुताबिक काम अगले सप्ताह में शुरू किया जा सकता है।

यातायात सुचारू रखने के लिए फ्लाईओवर के शुरू और खत्म होने पर कट बनाया गया है। सरिता विहार फ्लाईओवर एनसीआर के नोएडा और फरीदाबाद क्षेत्रों को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और बदरपुर से जोड़ता है। काम शुरू होने पर नोएडा व फरीदाबाद से आने वाले वाहन चालकों को पीक टाइम में जाम झेलना पड़ सकता है।

सरिता विहार फ्लाईओवर की दूसरी लेन पर बदलेगा एक्सपेंशन ज्वाइंट

सरिता विहार फ्लाईओवर का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 2001 में कराया था। पीडब्ल्यूडी की ओर से कराए जा रहे मरम्मत कार्य के तहत फ्लाईओवर के सात एक्सपेंशन ज्वाइंट बदले जाएंगे।

बेयरिंग और सतह की मरम्मत भी की जाएगी। मरम्मत का काम पिछले दो साल से लंबित है, जिसे अप्रैल 2022 में तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने मंजूरी दी थी। फ्लाईओवर की मरम्मत का काम इससे पहले मई, जून और जुलाई, अगस्त में निर्धारित किया गया था। तब से इसे कई बार स्थगित किया गया।

मई में लोकसभा चुनाव के चलते टाला गया तो वहीं जून में यातायात पुलिस से अनुमति नहीं मिली। जुलाई में एडवाइजरी जारी की गई तो कांवड़ यात्रा के चलते तब काम शुरू नहीं हो पाया। वर्षा से सरिता विहार अंडरपास में पानी भर जाता है, ऐसे में अगस्त में मानसून के चलते भी काम शुरू नहीं हो पाया था।

छठ पूजा पर घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर, चलेंगी 150 स्पेशल ट्रेनें; रेलमंत्री का एलान

छठ पूजा के लिए रेलवे ने तैयारी पूरी कर ली है। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार 7400 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। जबकि पिछले साल 4500 ट्रेनें चलाई गई थीं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 150 और ट्रेनें चलाने की तैयारी हैं। बिहार के चार बड़े स्टेशनों पर भीड़ संभालने का बेहतरीन प्लान बनाया गया है।

नई दिल्ली। दीपावली के बाद अब रेलवे स्टेशनों पर छठ पूजा में घर जाने वालों को भीड़ लगने लगी है। पूर्व दिशा के ट्रेनों में अधिक भीड़ है। भीड़ संभालने के लिए रेलवे स्टेशनों पर की गई व्यवस्था की जानकारी लेने शुक्रवार देर शाम रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। उन्होंने यात्रियों से बातकर व्यवस्था के बारे में उनसे सुझाव लिए।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस बार त्योहार के लिए पूरे देश में 7400 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 4,500 विशेष ट्रेनें चलाई गई थीं। इस बार 7435 ट्रेनें चलाई गईं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए 150 ट्रेनें और चलाने की व्यवस्था की जा रही है।

बिहार के चार बड़े स्टेशनों पर भीड़ संभालने का ये है प्लान

बृहस्पतिवार शाम तक 51 लाख लोग विशेष ट्रेनों का लाभ उठा चुके हैं। उन्होंने बताया कि नई दिल्ली, आनंद विहार टर्मिनल सहित देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, लखनऊ आदि में विशेष व्यवस्था की गई है। बिहार के चार बड़े स्टेशनों पर भीड़ संभालने के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से बात करते रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। सौ. रेलवे

ट्रेनों के बारे जानकारी देने के लिए लगाए गए स्क्रीन

देश के कई शहरों से बड़ी संख्या में यात्री पहुंच रहे हैं। इन स्टेशनों पर अतिरिक्त टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई हैं। नई दिल्ली और आनंद विहार टर्मिनल पर बड़ा पंडाल लगाकर अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया गया है, जिसमे पंखा, लाइट, पानी, शौचालय की व्यवस्था है। टिकट काउंटर और ट्रेनों के बारे जानकारी देने के लिए स्क्रीन लगाए गए हैं।

भाई -बहन के प्यार, जुड़ाव और एकजुटता का त्योहार भाई दूज

हमारे देश में हर महिला भाई दूज को अपने भाई के लिए अपना समर्थन और करुणा प्रदर्शित करने के लिए मनाती है। इस दिन सभी बहनें भगवान से अपने भाई के जीवन की खुशियों की कामना करती हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है क्योंकि यमुना को अपने भाई यमराज से यह वादा मिला था कि भाई दूज मनाने से ही यमराज के डर से छुटकारा मिल सकता है और यहां तक कि भाई और बहन के बीच प्यार या भावना बढ़ जाती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहारों से भरपूर खुशियां देते हैं। रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भाई-बहन के बंधन को मजबूत करती है।

- प्रियंका सौरभ

भाई दूज या यम द्वितीया दिवाली के दो दिन बाद मनाई जाती है। बहनें अपने भाइयों के लंबे जीवन के लिए प्रार्थना करने के लिए टीका समारोह में भाग लेती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं जो भाई-बहनों के बीच बंधन का सम्मान करते हैं। भाई दूज के कुछ अन्य नाम भाऊ बीज, भात्री द्वितीया, भाई द्वितीया या भथरू द्वितीया हैं। इस दिन को यम द्वितीया भी कहा जाता है, जो यहां कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को पड़ती है। यम द्वितीया पर, यमराज, मृत्यु के देवता, चित्रगुप्त और यम-दूत, भगवान यमराज के अनुयायियों के साथ पूजा की जाती है। भाई दूज एक हिंदू घटना है। यह दो शब्दों से बना है: ₹भाई,₹ जिसका अर्थ है ₹भाई₹, ₹दूज₹ के साथ, जो अमावस्या के बाद दूसरे दिन को संदर्भित करता है, जो उत्सव का दिन भी है। भाई-बहन के जीवन में यह दिन विशेष रूप से सार्थक होता है। भाई-बहनों के बीच गहन रिश्ते का सम्मान करने के लिए यह एक खुशी की घटना है। बहनें अपने भाइयों को अपने घर आने और मनपसंद व्यंजन बनाने के लिए आमंत्रित करती हैं। बहनें भी अपने भाइयों के स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और सभी बीमारियों और दुर्भाग्य से सुरक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। बदले में, भाई अपनी बहनों की देखभाल करने और उनकी आराधना करने के अपने दायित्वों को पूरा करते हैं।

भाई दूज एक महत्वपूर्ण त्योहार है जिसे पूरे भारत में बहुत जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। समारोह में भाइयों को उनके पसंदीदा भोजन या मिठाइयों के शानदार भोज के लिए आमंत्रित करने का काम शुरू होता है। पूरी घटना एक भाई के अपनी बहन की रक्षा के वादे का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि एक बहन भगवान से प्रार्थना करती है और अपने भाई की भलाई के लिए शुभकामनाएं करती है। परंपरागत रूप से संस्कार को समाप्त करने के लिए, बहनें अपने भाइयों के लिए चावल के आटे से एक आसन बनाती हैं। यहाँ भाई के माथे पर, सिंदूर से बना एक पवित्र टीका, दही, चावल के साथ लगाया जाता है। उसके बाद बहन अपने भाई की हथेलियों में कद्दू के फूल, पान, सुपारी या नकदी रखती है और पानी डालते हुए धीरे-धीरे श्लोकों का जाप करती है। उसके बाद वह आरती भी करती है। दक्षिण दिशा की ओर मुख किया हुआ दीपक जलता है और आकाश में उड़ती पतंग को देखना मनोकामना पूर्ण होने का एक अच्छा शगुन है। दावतों का स्वाद लेते हुए भाइयों को उनकी पसंदीदा मिठाई और पीने के लिए पानी दिया जाता है। कार्यक्रम में भाइयों और बहनों के बीच भाई दूज उपहारों का आदान-प्रदान किया जाता है, और बड़ों का आशीर्वाद मांगा जाता है।

हिंदू शास्त्रों के अनुसार, देवी यमुना अपने भाई भगवान यम के काफी करीब थीं, जो मृत्यु के देवता थे। उसे अपने भाई को देखने की तीव्र इच्छा थी क्योंकि उन्होंने एक-दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा था। जब भगवान यम दीवाली के दो दिन बाद अपनी बहन को बधाई देने पहुंचे, तो देवी यमुना ने भावना से अभिभूत होकर उनके लिए स्वादिष्ट भोजन पकाते समय उनके माथे पर टिक्का रखा। भगवान यम अपनी बहन के कृत्य से प्रभावित हुए और उन्हें वरदान मांगने का निर्देश दिया। देवी यमुना ने हँसते हुए उन्हें वर्ष में एक बार अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया, यह कहते हुए कि जिसकी बहन उसके माथे पर तिलक लगाएगी, वह अपने भाई भगवान यम से नहीं डरेगी क्योंकि उनकी बहन का प्यार उनकी रक्षा करेगा। भगवान यम ने इस उपकार और भाई दूज के त्योहार को पूरा किया, जो हिंदू धर्म की परंपरा और पांच दिवसीय दिवाली समारोह का एक महत्वपूर्ण घटक बन गया है। भाई दूज एक ऐसा

त्योहार है जो भाई और बहन के प्यार, जुड़ाव और एकजुटता का सम्मान करता है। यह आयोजन रक्षा बंधन के समान ही है और इसका एक ही लक्ष्य है। इस दिन को भाई-बहनों के बीच मिठाइयों या उपहारों के आदान-प्रदान किया जाता है। अपनी भक्ति के प्रतीक के रूप में और अपने भाइयों को बचाने के लिए, बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर टिक्का लगाया जाता है।

भाई दूज पूरे भारत में मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय अवकाश है। हालाँकि, इसे विभिन्न देश वर्गों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में, इसे 'भाऊ बीज' माना जाता है, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में, इसे 'भाऊ टीका' माना जाता है। इसे पश्चिम बंगाल में 'भाई फोटा' कहा जाता है। नेपाल में, इस व्यंजन को 'भाई तिहार' के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में हर महिला भाई दूज को अपने भाई के लिए अपना समर्थन और करुणा प्रदर्शित करने के लिए मनाती है। इस दिन सभी बहनें भगवान से अपने भाई के जीवन की खुशियों की कामना करती हैं। यह व्यापक रूप से माना जाता है क्योंकि यमुना को अपने भाई यमराज से यह वादा मिला था कि भाई दूज मनाने से ही यमराज के डर से छुटकारा मिल सकता है और यहां तक कि भाई और बहन के बीच प्यार या भावना बढ़ जाती है। बदले में भाई अपनी बहनों को उपहारों से भरपूर खुशियां देते हैं। रक्षाबंधन की तरह भाई दूज भाई-बहन के बंधन को मजबूत करती है।

राखी बांधना एक भाई की अपनी बहन को बुरी ताकतों से बचाने और उसकी रक्षा करने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। भाई दूज के दौरान अपने भाई के माथे पर टीका लगाकर, बहन हर तरह से अपने भाई की रक्षा करने का वादा करती है। बहनें अपने भाई के लिए आरती करती हैं और फिर उसके माथे पर लाल टीका लगाती हैं। भाई दूज की तुलना रक्षा बंधन के भारतीय उत्सव से की जाती है, जिसमें यह एक भाई और एक बहन के बीच मौजूद चिरस्थायी रिश्ते की याद दिलाता है। इस विशेष आयोजन में, भाई अपनी बहनों से मिलते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे ठीक हैं और उपहार या मिठाइयाँ बाँटते हैं।

भैया दूज

भैया दूज प्रेम का,
हृदय का त्योहार !
इसमें बसती द्रौपदी,
है कान्हा का प्यार !!

कहती हमसे दूज ये,
तुच्छ है सभी स्वार्थ !
बहनों की शुभकामना,
तुमको करे सिद्धार्थ !!

भाई-बहना नेह के,
रिश्तों के आधार !
इस रिश्ते के सामने,
हीरे हैं बेकार !!

बहना मूरत प्यार की,
मांगे ये वरदान !
भाई को यश-बल मिले,
लोग करे गुणगान !!

भाई से छोटे सभी,
सोना, मोती, सीप !
दुनिया मुंह जब मोड़ती,
होता यही समीप !

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार

पेट की चर्बी को तेजी से कम करता है लौकी का जूस, रोजाना पीने से मिलते हैं कई बेमिसाल फायदे

लौकी भारत चीन समेत पूरी दुनिया में उगाई जाने वाली एक बहुत ही टेस्टी सब्जी है जिसका इस्तेमाल सब्जी से लेकर पकौड़े खीर हलवा और रायता बनाने तक होता है। इसमें भूरपूर मात्रा में फाइबर विटामिन सी मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। यही वजह है कि रोजाना इसका जूस (Bottle Gourd Juice) पीने से सेहत को कई फायदे मिलते हैं।

लौकी एक ऐसी सब्जी है जो भारत और चीन समेत दुनिया भर के ज्यादातर हिस्सों में उगाई जाती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिहाज से भी काफी फायदेमंद (Bottle Gourd Juice Benefits) है। लौकी का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के व्यंजनों जैसे सब्जी, जूस, कोफ्ते, पकौड़े, खीर, हलवा और रायता बनाने में किया जाता है। ये व्यंजन न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होते हैं। विशेष रूप से, लौकी का जूस एक नेचुरल एनर्जी ड्रिंक के रूप में जाना जाता है जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत को बढ़ावा देता है। बता दें, वजन घटाने में भी लौकी का जूस (Bottle Gourd Juice For Weight Loss) काफी मददगार होता है। आइए जानते हैं कि लौकी का जूस सेहत के लिए इतना फायदेमंद क्यों है।

पोषक तत्वों का भंडार है लौकी

लौकी एक बेहद पौष्टिक सब्जी है। इसमें पानी, फाइबर और विटामिन सी, बी6, फोलेट, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा, लौकी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। लौकी का जूस विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है। यह शरीर को एनर्जी देता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी काफी मदद करता है।

डाइजेशन को बनाए बेहतर

लौकी का जूस पाचन तंत्र के लिए वरदान है।

यह फाइबर से भरपूर होता है, जो पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। इसके नियमित सेवन से कब्ज और पेट संबंधी अन्य समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। लौकी का रस पेट को स्वस्थ रखने में भी अहम भूमिका निभाता है।

वजन घटाने में मददगार

फाइबर से भरपूर लौकी में इसमें कैलोरी कम होती है,जो लंबे समय तक पेट के भरा होने का एहसास कराती है, और यही वजह है कि भूख कम लगने से वजन काबू में रहता है क्योंकि आप ओवरईटिंग से बच जाते हैं।

हार्ट को रखे हेल्दी

लौकी में मौजूद पोटैशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, जो हृदय स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल को संतुलित रखता है, जिससे दिल की बीमारियों का जोखिम भी कम होता है।

हेल्दी स्किन

एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर लौकी के जूस का नियमित सेवन स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करता है, जिससे इसे ग्लोइंग बनाए रखने में मदद मिलती है। इसके साथ ही ये स्किन को मॉइस्चराइज करता है, जिससे झुर्रियां कम होती हैं।

शरीर को ठंडक और हाइड्रेशन

लौकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद सब्जी है। इसमें 92% तक पानी की मात्रा होती है, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करती है। गर्मियों में लौकी का जूस पीने से शरीर को प्राकृतिक ठंडक मिलती है। यह न केवल प्यास बुझाता है बल्कि शरीर के तापमान को भी संतुलित रखता है।

स्ट्रेस में कमी

लौकी का जूस आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद पोषक तत्व तनाव को कम करने में मदद करते हैं और नींद की गुणवत्ता को बेहतर बनाते हैं। नियमित रूप से लौकी का जूस पीने से हम मानसिक रूप से शांत और तरोताजा महसूस करते हैं।

10 स्नैक्स, जिन्हें तलने के बजाय बेक करके खा सकते हैं आप! स्वाद में भी नहीं आएगी कोई कमी

अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते आज ऑयली फूड्स का सेवन कई बीमारियों की वजह बन रहा है। ऐसे में बेकिंग एक हेल्दी ऑप्शन है और आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ स्नैक्स ऐसे हैं जिन्हें आप तलने के बजाय बेक करके ही खा सकते हैं और वो भी बिना स्वाद के साथ समझौता किए! जी हां आइए जानते हैं ऐसे 10 स्नैक्स के बारे में।

नई दिल्ली। आजकल मिलावट के कारण तले हुए फूड आइटम्स का सेवन सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित हो रहा है। ज्यादा तेल और हानिकारक तत्वों के कारण ये मोटापा, डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियों और पाचन संबंधी समस्याओं का कारण बन रहे हैं। ऐसे में सेहत को लेकर जागरूक लोग अब हेल्दी ऑप्शन्स की ओर रुख कर रहे हैं। बेक्ड भोजन एक ऐसा ही स्वादिष्ट और सेहतमंद विकल्प है। बेकिंग में कम तेल का इस्तेमाल होता है, जिससे कैलोरी कम होती है और यह हार्ट के लिए भी अच्छा होता है। आप अपनी पसंदीदा डिशेस को बिना तेल के बेक करके भी उतना ही स्वादिष्ट बना सकते हैं।

1) **समोसा:** समोसा लगभग पूरे इंडिया का एक फेवरेट नाश्ता है जिसे आप बेक करके भी खा सकतें हैं। इन्हें बेक करने से ये लाइट और ऑयल फ्री बन सकते हैं, साथ ही इनका स्वाद भी बरकरार रहता है।

2) **पकौड़े:** बेसन के पकौड़ों को बेक करने से वे न केवल क्रिस्पी बनते हैं, बल्कि इनमें तेल की मात्रा भी कम होती है, जिससे ये ज्यादा हेल्दी बन जाते हैं।

3) **फ्रेंच फ्राइज:** तले हुए फ्रेंच फ्राइज की जगह आप बेक्ड फ्राइज खाकर कम फैट्स का सेवन कर सकते हैं और इसका स्वाद भी बना रहता है।

4) **कचौड़ी:** कचौड़ी को बेक करना इसे पाचन के लिए आसान और कम कैलोरी वाला बनाता है, जिससे यह एक बेहतरीन स्नैक बन जाती है।

5) **चिकन नगेट्स:** बेक्ड चिकन नगेट्स तले हुए से ज्यादा प्रोटीन और कम फैट वाले होते हैं। इसलिए, आप इन्हें बिना तेल के बेक करके खा सकते हैं। ये सेहत के लिहाज से बेहतर होने के साथ-साथ काफी टेस्टी भी होते हैं।

6) **पनीर टिक्का:** पनीर टिक्का को बेक करना इसे ज्यादा पौष्टिक और स्वादिष्ट बनाता है। इसके साथ आप सब्जियों को भी शामिल कर सकते हैं।

7) **फिश टिक्का:** मछली को बेक करने से उसका स्वाद बढ़ता है और यह सेहत के लिहाज से भी ज्यादा पौष्टिक हो जाती है।

8) **बेक्ड पास्ता:** पास्ता को बेक करके उसमें सब्जियों और कम फैट वाले चीज का इस्तेमाल करें। यह एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है।

9) **चिप्स:** बच्चों का फेवरेट चिप्स, बेकिंग के जरिए हल्का और क्रिस्पी बनाया जा सकता है, जो क्रिस्पी होने के साथ-साथ टेस्टी और हेल्दी भी होते हैं।

10) **मसाला मूंगफली:** बेक करने वाले स्नैक्स में मसाला मूंगफली को भी बेहद खास है। ये क्रिस्पी तो बनती ही हैं, साथ ही इसमें तेल की मात्रा भी नहीं के बराबर होती है।

इन बेक्ड स्नैक्स को अपनाकर आप अपनी डाइट में शामिल करके स्वाद से समझौता किए बिना सेहत का ख्याल रख सकते हैं और बिना किसी एक्स्ट्रा ऑयल के मजेदार खाने का लुत्फ भी उठा सकते हैं।

हेयरफॉल से छुटकारा दिलाकर बालों की ग्रोथ बढ़ाने में मदद करेंगे 7 फूल, नोट करें इस्तेमाल का सही तरीका

फूलों का इस्तेमाल सजावट के लिए तो सभी करते हैं लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये बालों की खूबसूरती में भी चार चांद लगा सकते हैं? दरअसल गुड़हल गुलाब चमेली लैवेंडर और गेंदे जैसे फूल आपके बालों को घना मजबूत और चमकदार बनाते हैं। इनके तेल या पेस्ट से सिर की मालिश करने से आपको कई बेमिसाल फायदे मिल सकते हैं।

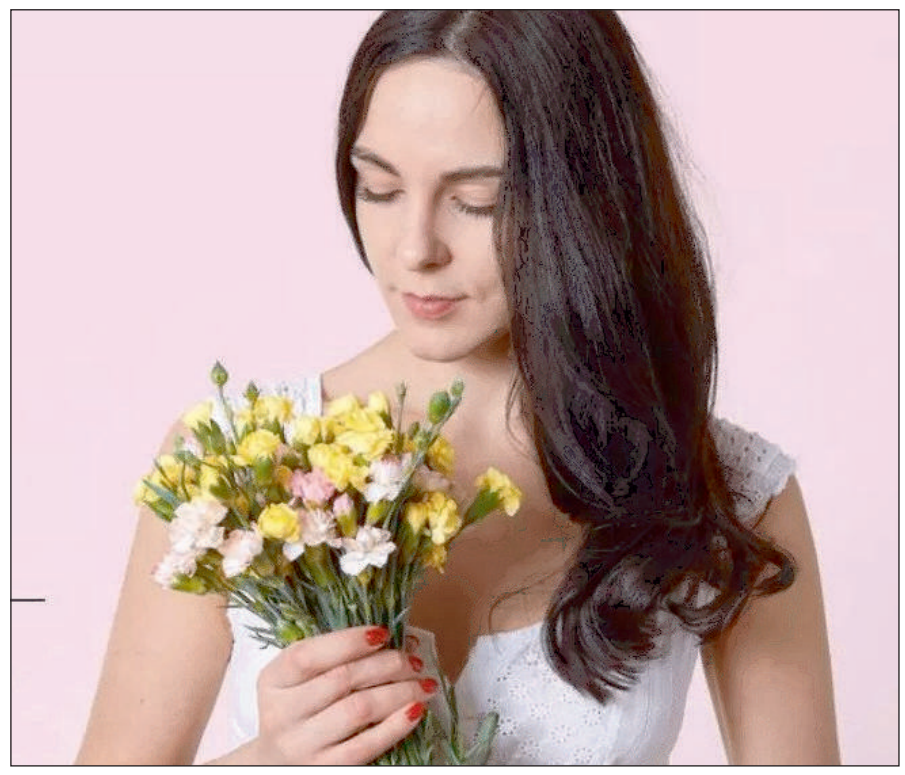

फूल सिर्फ गुलदस्ते को खूबसूरत बनाने का काम ही नहीं करते, बल्कि ये हमारे बालों को भी हेल्दी और प्रॉब्लम-फ्री रखते हैं। इनमें मौजूद प्राकृतिक तत्व बालों को पोषण और मजबूती (Flowers For Hair Growth) देते हैं, जिससे बाल काले, घने, लंबे और चमकदार बनते हैं। फूलों से बने तेल, पेस्ट या गुलाब जल बालों को पूरी तरह से पोषण देने का काम करते हैं। इनका नियमित इस्तेमाल बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बालों के टूटने, गिरने या रूखे होने की समस्या को दूर करता है। आइए जानते हैं कि कौन-से फूल बालों के लिए फायदेमंद होते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।

1) **गुड़हल के फूल**

यह फूल बालों की ग्रोथ बढ़ाने में बेहद प्रभावी है। गुड़हल के फूल और पत्तों का पेस्ट बनाकर बालों की जड़ों में लगाएं, 30 मिनट बाद नॉर्मल पानी से वॉश करें। गुड़हल का तेल भी स्कैल्प में मसाज के लिए उपयोगी है।

2) **गुलाब के फूल**

गुलाबजल में हाइड्रेटिंग गुण पाया जाता है जो बालों को नमी प्रदान करते हैं। इसे बालों में स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह स्कैल्प की ताजगी को बढ़ाता है और बालों को नेचुरल तरीके से पोषण देते हुए सॉफ्ट बनाता है।

3) **चमेली के फूल**

चमेली का तेल एंटी-बैक्टीरियल और मॉइस्चराइजिंग गुणों से भरपूर है, जो बालों को मजबूत बनाता है।इसे नारियल या जैतून के तेल के साथ मिलाकर बालों पर लगाएं।

4) **लैवेंडर के फूल**

लैवेंडर मेंटल स्ट्रेस कम करने और बालों की ग्रोथ को बेहतर बनाने में सहायक है। लैवेंडर के तेल को जैतून या नारियल तेल में मिलाकर हफ्ते में एक बार मसाज करें।

5) **गेंदे के फूल**

गेंदे का फूल रूखे-सूखे और डैमेज बालों के लिए सबसे बेस्ट है। बादाम, नारियल या जैतून के तेल को गर्म करके इसमें पहले से साफ करके रखी हुई गेंदे की पंखुड़ियों को डालकर गर्म करें और फिर आंच बंद कर कुछ दिनों के लिए छोड़ दें बाद में छानकर इस्तेमाल करें।

6) **रोजमेरी के फूल**

रोजमेरी का तेल बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है। इसे जैतून के तेल में मिलाकर लगाएं और कुछ घंटों बाद धो लें।

7) **कमल के फूल**

कमल का पेस्ट बालों में नमी और मजबूती लाता है। इसका पेस्ट बनाकर स्कैल्प पर लगाएं, यह बालों को टूटने से रोकता है।

पहाड़ों से मैदान तक आतिशबाजी से जहरीली हुई हवा, देश के ज्यादातर शहरों में प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में

परिवहन विशेष न्यूज

दीपावली पर हुई आतिशबाजी के कारण पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हवा जहरीली हो गई। दिल्ली में गुरुवार को पटाखे जलने से पहले शाम छह-सात बजे तक प्रदूषण अपेक्षाकृत कम था लेकिन आठ बजे के बाद जब पटाखे जलने शुरू हुए तो इसमें इजाफा होने लगा। यूपी के कई शहरों में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बिहार के शहरों में भी यही स्थिति रही।

नई दिल्ली। दीपावली पर हुई आतिशबाजी के कारण पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक हवा जहरीली हो गई। लोगों ने पाबंदियों को धता बता जमकर पटाखे छोड़े, जिससे प्रदूषण काफी बढ़ गया। एक दिन पहले और दीपावली के दिन के एक्यूआइ में काफी अंतर रहा। ज्यादातर शहरों में यह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। हालांकि तेज हवा चलने के कारण इस बार एक्यूआइ थोड़ा कम रहा, अन्यथा स्वास्थ्य के लिए गंभीर स्थिति हो सकती थी।

मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की दिशा उत्तर-पश्चिमी थी, जिसकी गति पूर्वाहन 11:30 बजे से शाम छह बजे तक 12 से 16 किमी प्रति घंटा रही। इसके बाद शुक्रवार सुबह तक तीन से सात किमी प्रति घंटा दर्ज की गई।

दिल्ली में आधी रात के बाद तक खूब पटाखे जले

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आधी रात के बाद तक खूब पटाखे जले, लेकिन कहीं का भी एक्यूआइ गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचा। दिल्ली में गुरुवार को पटाखे जलने से पहले शाम छह-सात बजे तक प्रदूषण अपेक्षाकृत कम था, लेकिन शाम आठ बजे के बाद जब पटाखे जलने शुरू हुए, तो इसमें इजाफा होने लगा। यह हर घंटे बढ़ता गया। शाम सात बजे दिल्ली का एक्यूआइ 327 यानी बहुत खराब श्रेणी में था। रात 11 बजे के लगभग यह 330 दर्ज हुआ।

शुक्रवार सुबह सात बजे 362 तक हो गया। चंडीगढ़ में प्रशासन ने रात आठ से दस बजे तक आतिशबाजी की अनुमति दी थी, लेकिन काफी पहले ही यह शुरू हो गई और देर रात तक जारी रही। इससे एक्यूआइ 395 पहुंच गया। एक दिन पहले यह 250 था। सामान्य दिनों में 140 रहता है।

पहाड़ों पर भी जमकर आतिशबाजी हुई

उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दीपावली के बाद वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बिहार के शहरों में भी यही स्थिति रही। पटना में सामान्य दिनों की तुलना में दीपावली की रात वायु प्रदूषण में वृद्धि दर्ज की गई। कोलकाता में जमकर आतिशबाजी हुई। पहाड़ों पर भी जमकर आतिशबाजी हुई।

देहरादून का एक्यूआइ 270 दर्ज किया गया

दीपावली की रात देहरादून का एक्यूआइ 270 दर्ज किया गया। एक दिन पहले यह 159 था। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अमित पोखरियाल के अनुसार हवा में प्रदूषण कम करने के लिए देहरादून में तीन और ऋषिकेश में एक ड्रोन के माध्यम से पानी का छिड़काव किया गया। इससे वायु प्रदूषण में कमी आई। हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी का प्रदूषण स्तर देश के शीर्ष 15 शहरों में रहा। बद्दी का एक्यूआइ दीपावली को 351 रहा।

एक दिन पहले और दीपावली के दिन वायु प्रदूषण की स्थिति (एक्यूआइ में)

चंडीगढ़	250	395
दिल्ली	307	330
देहरादून	159	270
बद्दी	223	351
पटना	54	188

'15 दिन में हालात नहीं सुधरे तो...', सीएम आवास पहुंचकर स्वाति मालीवाल ने दी सरकार को चेतावनी

राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने द्वारका विधानसभा के सागरपुर इलाके का दौरा किया जहां स्थानीय निवासियों को महीनों से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी क्रम में उन्होंने एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के घर से इस गंदे पानी का नमूना इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि जनता के दर्द को सरकार समझे और तुरंत सुधार करे।

नई दिल्ली। दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने शनिवार को गंदे पानी का नमूना सीएम आवास के बाहर रखकर इसे दीवाली का विशेष उपहार बताते हुए दिल्ली सरकार को तत्काल समाधान की मांग की।

स्वाति ने द्वारका विधानसभा के सागरपुर इलाके का दौरा किया, जहां स्थानीय निवासियों को महीनों से गंदा और बदबूदार पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इसी क्रम में उन्होंने एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी के घर से इस गंदे पानी का नमूना इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि जनता के दर्द को सरकार समझे और तुरंत सुधार करे।

अगली बार पानी के टैंकर से छिड़काव कराऊंगी: स्वाति

राज्यसभा सदस्य ने मथुरा रोड स्थित सीएम आवास के बाहर गंदे पानी से भरे बोतले से कुछ हिस्सा वहीं पर गिराया और आधा सीएम अवास के बाहर रख दिया। मालीवाल ने कहा कि अगर हालात 15 दिन में नहीं सुधरे तो अगली बार पानी का टैंकर लाकर मुख्यमंत्री के निवास पर छिड़काव किया जाएगा।

मालीवाल ने सीएम आतिशी के निवास पर गंदे पानी की बोतल छोड़ते हुए कहा कि यह पानी खुद पीकर देखिए ताकि जनता के दर्द का अहसास हो सके। अगर दिल्ली सरकार जल्द ही पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती है, तो जनता के हक के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।

2015 से सुन रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा: स्वाति

स्वाति मालीवाल ने कहा, ₹सागरपुर, द्वारका के लोगों ने मुझे फोन किया था कि वहां की स्थिति बहुत खराब है। मैं एक घर में गई और वहां काले पानी की आपूर्ति की जा रही थी। मैंने उस काले पानी को एक बोतल में भर लिया और मैं वो पानी यहां मुख्यमंत्री आवास पर लाई हूं। 2015 से हम सुन रहे हैं कि अगले साल सब ठीक हो जाएगा।₹

उनको शर्म नहीं आती, दिल्ली ये पानी पीएगा: स्वाति

उन्होंने कहा कि वो काला पानी जो मैं लेकर आई हूं, यह देखकर उनको शर्म नहीं आती कि क्या ये दिल्ली पीएगा? मुख्यमंत्री जी, ये तो एक नमूना था, अगर पंद्रह दिन के अंदर पूरी दिल्ली की पानी की सप्लाई ठीक नहीं की तो मैं इतना पानी भर कर लाऊंगी कि वो इस पानी से नहा सकती हैं।

उन्होंने कहा कि छठ पूजा नजदीक है, कल दिवाली थी और दिल्ली का ये हाल है। कौन इस पानी को पीकर जिंदा रह सकता है? मुख्यमंत्री जल मंत्री भी हैं। क्या उनका काम हर दिन दस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मजाक उड़ाना है?

दिल्ली में छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश घोषित

परिवहन विशेष न्यूज

सूत्रों के अनुसार उपराज्यपाल की चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने लिया दिल्ली में छठ पूजा के अवसर पर 7 नवंबर 2024 को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला।

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखकर इस संबंध में अनुरोध किया और लिखा- छठ पूजा एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है जो चार दिनों तक मनाया जाता है। तीसरा दिन जब अस्ताचल सूर्य भगवान को अर्घ्य अर्पित किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है। पहले इस दिन को रिस्ट्रिक्टेड अवकाश के रूप में घोषित किया हुआ है, मेरा आग्रह है कि सरकार 7 नवंबर 2024 (गुरुवार) को पूर्णकालिक अवकाश के रूप में घोषित करे और इससे संबंधित फाइल शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित की जाए। पत्र प्राप्त होने के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने को कहा। पत्र में कहा छठ पूजा दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। इसके उपरांत दिल्ली सरकार ने 7 नवंबर 2024 को 'छठ पूजा' के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया।

सीएम आतिशी ने कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी है कि दिल्ली सरकार ने फैसला ले लिया है कि 7 नवंबर को छठ के त्योहार पर सार्वजनिक छुट्टी होगी। अब सभी पूर्वांचली भाई-बहन धूम-धाम से छठ का त्योहार मना सकते है।

दिल्ली-एनसीआर में धूमधाम से मनाया जाता है छठ मालूम हो कि लोक आस्था के इस पर्व छठ को दिल्ली - एनसीआर में भी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दिल्ली - एनसीआर में पूर्वांचल समाज के लोग काफी बड़ी संख्या में रहते हैं। बड़ी संख्या में लोग यमुना किनारे और बहुत से लोग घर के आसपास छोटे-छोटे तालाब बनाकर पूजा करते हैं।

दिल्ली में सांस लेने में हो रही परेशानी, अगले तीन दिनों तक राहत नहीं कई इलाकों में एक्यूआई 400 पार

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। शनिवार को दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स 300 से अधिक दर्ज किया गया। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी। आनंद विहार और सोनिया विहार में एयर इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह प्रदूषण के तेवर थोड़े ढीले रहे। इस वजह से सुबह एयर इंडेक्स 300 से नीचे खराब श्रेणी में आ गया था, लेकिन बाद में हवा की दिशा बदलने और बेहद धीमी गति से हवा चलने के कारण एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हो गया। इस वजह से दिल्ली का औसत एयर इंडेक्स बढ़कर 300 से अधिक पहुंच गया। इस वजह से दिल्ली में दिन में हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रही। कई इलाकों में यह 400 के पार हो गया है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार अभी प्रदूषण से खास राहत मिलने की संभावना नहीं है। इस वजह से अगले तीन दिनों तक हवा की गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी रहेगी। वहीं वर्तमान हालात के कारण राजधानी में बच्चों और बुजुर्गों के लिए स्थिति और खराब हो गई है। सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन की शिकायतें आ रही है।

रात आठ बजे के बाद खराब होती गई गुणवत्ता

दिल्ली में एक नवंबर को एयर इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में 339 था, लेकिन शनिवार सुबह एयर इंडेक्स घटकर 290 पहुंच गया था। दिन में 11.30 बजे के बाद हवा की दिशा दक्षिण पश्चिम से बदलकर उत्तर पश्चिम की तरफ से हो गई। इसके बाद एयर इंडेक्स बढ़ना शुरू हुआ और शाम चार बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 316 पहुंच गया, जो पिछले दिन के मुकाबले 23 अंक कम है। लेकिन रात आठ बजे दिल्ली का एयर इंडेक्स 350 पहुंच गया था।

आनंद विहार और सोनिया विहार का AQI 400 पार

आनंद विहार और सोनिया विहार में रात आठ बजे एयर इंडेक्स क्रमश 411 और 402 था। इस वजह से इन दोनों इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। एनसीआर के शहरों में गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही। इसके अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा व गुरुग्राम एयर इंडेक्स खराब श्रेणी में रहा। एनसीआर में फरीदाबाद में एयर इंडेक्स सबसे कम मध्यम श्रेणी में 166 रहा।

छठ पूजा को लेकर आप ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा, छठ घाट बनाने से रोकने का लगाया आरोप

छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी पर डीडीए के माध्यम से पूर्वांचलवासियों को छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक शख्स डीडीए पर घाट बनाने के लिए गेट नहीं खोलने का आरोप लगा रहा है। इस मामले पर सीएम आतिशी और सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर हमला बोला है।

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने बीजेपी पर डीडीए के माध्यम से पूर्वांचलवासियों को छठ घाट बनाने से रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल, मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक शख्स डीडीए पर घाट बनाने के लिए गेट नहीं खोलने का आरोप लगा रहा है।

सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर लिखा- चिराग दिल्ली और आस पास के पूर्वांचल भाइयों का छठ घाट भाजपा शासित DDA रोक रही है। पूर्वांचल के सम्मान के लिए, पूर्वांचल के भाइयों के हक की आवाज उठाने मैं आज 5 बजे सतपुला ग्राउंड, चिराग दिल्ली जाऊंगा।

सीएम आतिशी ने बोला हमला

वहीं सीएम आतिशी ने भी एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा- भाजपा पूर्वांचलियों से नफरत करती है। इनकी राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि ये, ग्रेटर कैलाश में DDA के माध्यम से छठ घाट पर रोक लगा रहे है। आस्था के महापर्व छठ को लेकर ऐसी ओछी राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी, भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा।

बीजेपी पूर्वांचलियों से नफरत करती है: संजय सिंह

वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा- मैं बार बार कहता हूं कि BJP पूर्वांचलियों से नफरत करती है। ग्रेटर कैलाश में BJP पार्षद ने छठ घाट तोड़ा था। अब BJP वाले DDA के माध्यम से छठ घाट पर रोक लगा रहे हैं। छठ घाट से खिलवाड़ किया तो अंजाम बुरा होगा।

बता दें, सीएम आतिशी ने छठ पूजा को लेकर 7 नवंबर को दिल्ली में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने 7 नंबर को सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा करने के लिए सीएम आतिशी को चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने छुट्टी की फाइल जल्द भेजने की अपील भी की थी।

'यूपी-हरियाणा के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ रहा', केजरीवाल ने बीजेपी से क्यों किया सवाल?

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने सवाल किया है कि अगर मोदी सरकार की आयुष्मान भारत योजना इतनी अच्छी है तो फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली क्यों आना पड़ता है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पूरे देश के लोगों का इलाज करेंगे उनका दिल से स्वागत है।

नई दिल्ली। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं जब 10 साल पहले लोगों के घरों में जाता था तो वो मुझे अपने पानी-बिजली के 8000-10000 के बिल दिखाते थे और कहते थे कि ये बिल भरें या बच्चों को पढ़ायें। मैंने कहा था कि एक बार सरकार बना दो तो सब बिल माफ कर दूंगा और सरकार बनने के बाद ही सारे बिजली और पानी के पुराने बिल माफ कर दिए।

उन्होंने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि केजरीवाल ने दिल्ली में 'आयुष्मान भारत योजना' लागू नहीं की, उत्तर प्रदेश में तो लागू है ना लेकिन वहां के मरीज भी दिल्ली आकर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में इलाज करवाते हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि पूरे देश के लोगों का इलाज करेंगे, उनका दिल से स्वागत है। अगर मोदी जी को योजना इतनी अच्छी होती तो फिर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता?

बीजेपी के एलजी ने सिर्फ दिल्ली का काम रोका: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि जब मैं जेल गया तो LG चला रहे थे दिल्ली को, जब LG के पास पॉवर थी तो कुछ अच्छा काम करते। कोई एक काम बता दो जो तुम्हारी BJP के LG ने किया हो दिल्ली के अंदर। उन्होंने काम रोकने का काम किया, कूड़ा फैला दिया चारों तरफ, सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवर फ्लो कर रहे हैं। अब चिंता मत करना केजरीवाल बाहर आ गया है तुम्हारे सारे काम करा दूंगा।

बीजेपी की सरकारें लोगों को इलाज नहीं दे पा रही: केजरीवाल

उन्होंने कहा कि 24 घंटे, 365 दिन नफरत की राजनीति करने वाली BJP की नफरती सोच का एक और सबूत। BJP Fake IT Cell की नफरती सोच समझें। AAP सरकार और दिल्ली की जनता के लिए गर्व की बात है कि वो अपने उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत पूरे देश के भाई-बहनों का इलाज कर रहे हैं वो भी तब जब खुद बीजेपी की राज्य सरकारें इन्हें इलाज तक नहीं दे पा रही हैं। अब अगर बीजेपी इन राज्यों के लोगों को इलाज नहीं दे सकती तो दिल्ली सरकार अपने देश के सभी राज्यों के भाई-बहनों का दिल से स्वागत कर, सभी का इलाज करेगी।

कूलर बनाने की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, अग्निशमन विभाग की टीम बुझाने में जुटी

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र में कूलर की कैबिनेट बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। घटना की जानकारी तत्काल दमकल की टीम को दी गई थी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई है। आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

साहिबाबाद। मोहन नगर औद्योगिक क्षेत्र के हर्षा कंपाउंड की कूलर बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने के सूचना पर अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर अग्निशमन कर्मी आग को बुझाने के काम में लग गए। फैक्ट्री में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला।

अग्निशमन कर्मियों को आग बुझाने के लिए फैक्ट्री की दीवार को तोड़ना पड़ा। आग में जल करे छोटे हाथी को रस्सी बांधकर निकालने की कोशिश की गई। जब वह नहीं निकाला तो बुलडोजर की सहायता से उसे बाहर निकाला गया। आग पर काबू पाने की कोशिश अभी भी जारी है।

सभी कामगार पूजा के लिए गए हुए थे घर

फैक्ट्री मालिक विजय यादव ने बताया कि दोपहर लगभग दो बजे वे व सभी कामगार पूजा करने के बाद सभी अपने घर चले गए थे। फैक्ट्री की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति मौजूद था। चार बजे के आसपास आग लगने की सूचना मिलने के बाद वे मौके पर पहुंचे। आग पूरी फैक्ट्री में लग चुकी थी।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के बताया कि फैक्ट्री में आग लगनेसहायात की सूचना अग्निशमन की गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग बुझाने के लिए वैशाली, साहिबाबाद, नोएड़ा, लोनी और गाजियाबाद से अग्निशमन की गाड़ियां बुलाई गई। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है।

लोनी बॉर्डर में भी एक प्लॉट में छह दिन से आग

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र कृष्णा विहार फेस दो स्थित एक प्लॉट में पड़े रसायनयुक्त मिश्रण में छह दिन से आग लग रही है। पिछले छह दिन से अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी है। बताया जा रहा है कि रसायन का मिश्रण होने के कारण यह आग नहीं बुझ रही है। इससे धुआं फैल रहा है। लोनी बार्डर कृष्णा विहार कॉलोनीवासियों ने बताया कि कृष्णा विहार मिश्रण में सात दिन पूर्व अचानक आग लग गई। सुलगती आग से जहरीला धुंआ निकलता देख लोगों ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई।

30 सितंबर को फिर से धुआं उठना शुरू हुआ

29 सितंबर को विभाग की एक गाड़ी पहुंची और आग को शांत करा दिया। इसी अगले दिन 30 सितंबर को फिर से इसमें धुआं उठना शुरू हो गया। अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इसी तरह पिछले छह दिन से अग्निशमन विभाग की टीम प्रतिदिन आग बुझाकर आ जाती है, लेकिन अगले दिन फिर से इस मिश्रण में आग लग जाती है। इसके धुएं से लोगों का दम घुट रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस कंट्रोल रूम को दी।

सुध नहीं ले रहे प्रशासनिक अधिकारी

लोगों ने कहा कि करीब छह दिन से आग सुलग रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुध नहीं ली । लोग जहरीले धुएं में सांस ले रहे हैं। अधिकारी शनिवार दोपहर उपजिलाधिकारी आरके शुक्ला, लोनी नगरपालिका अधिकारी कृष्ण कांत मिश्रा मय पालिका टीम के साथ मौके पर पहुंचे। लोगों को समस्या दूर करने का आश्वासन दिया।

कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम आग पर काबू पाया गया है। संबंधित विभागों को पत्र लिख कर जांच कर कार्रवाई के लिए कहा गया है। - राजेंद्र कुमार शुक्ला, लोनी उपजिलाधिकारी

जूते की दुकान में लगी भीषण आग, फ्लैट में फंसे लोगों का किया रेस्क्यू

साहिबाबाद में दिवाली के दिन भीषण आग ने तबाही मचा दी। इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के ज्ञान खंड 1 में एक जूते की दुकान में आग लग गई जो ऊपर बने दो फ्लैट तक पहुंच गई। अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आग से जूते का शोरूम पूरी तरह से जलकर राख हो गया लेकिन किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है।

साहिबाबाद। दीपावली के दिन बृहस्पतिवार को इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के ज्ञान खंड 1 में जूते की दुकान में आग लग गई। आज दुकान के ऊपर बने दो फ्लैटों तक पहुंच गई। अग्निशमन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला।

वही, राजेंद्र नगर औद्योगिक क्षेत्र, क्रॉसिंग रिपब्लिक, शास्त्री नगर, लोनी चोपड़ा मंदिर के पास समेत कई स्थानों पर आग लगी। सभी जगह अग्निशमन कर्मियों ने पहुंचकर आग पर बुझाई। आग से कोई जनहानि नहीं हुई है।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की पांच गाड़ियां

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब 9:00 बजे फायर स्टेशन वैशाली पर सूचना मिली कि इंदिरापुरम कोतवाली क्षेत्र के ज्ञान खंड एक स्थित बिल्डिंग में आग लग गई है। सूचना पर वह पांच गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंचे।

आग दो मंजिला बिल्डिंग में जूते के शोरूम में लगी हुई थी। ऊपर फ्लैट में लोग फंसे हुए थे। अग्निशमन कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। आग बुझाने का काम शुरू किया। आग से जूते का शोरूम पूरी तरह से चल गया। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है।

जिले में 60 जगह आग लगने की मिली सूचना

वैशाली फायर स्टेशन : 21
कोतवाली : 17
मोदीनगर: 01
लोनी :07
साहिबाबाद :17

प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट बताकर ठगी

गुजरात के धोलेरा सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर विजयनगर गाजियाबाद के दो लोगों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। एक पीड़ित से 59 लाख रुपये की ठग लिए गये।। शिकायत करने के बाद पुलिस ने एक सेवानिवृत्त सूबेदार मेजर समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोप है कि नेक्सा एवरग्रीन कंपनी के अधिकारियों ने निवेश के नाम पर लोगों से पैसे लिए थे।

शिकायतकर्ता भाऊराव देवरस कॉलोनी के ज्ञानेश राजा ने इस मामले के संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि 2022 में एक परिचित के माध्यम से उन्हें धोलेरा सिटी के बारे में जानकारी मिली थी। वहां नेक्सा एवरग्रीन कंपनी द्वारा 1800 बीघा जमीन खरीदने और उस पर प्रोजेक्ट को शुरू करने की बात कही गई।

नोएडा एयरपोर्ट से सिंगापुर एयरलाइंस शुरू करेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें, आ गई तारीख

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। इस साल के अंत तक यानी नवंबर में एयरपोर्ट का ट्रायल रन शुरू होने के आसार हैं। बता दें एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 को विमान सेवा शुरू होने के पहले दिन से ही तीन अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा 25 घरेलू और दो कार्गो सेवाएं शुरू हो जाएंगी। एक क्लिक में पढ़ें सारा अपडेट।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करेगी। पहले दिन दोनों एयरलाइंस के विमान ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए उड़ान भरेंगे। इसके लिए इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आइएटीए) ने स्वीकृति दे दी है।

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लि. के साथ अनुबंध के बाद दोनों एयरलाइंस को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा शुरू करने के लिए आइएटीए में आवेदन किया गया था। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विमान सेवा शुरू होने का समय नजदीक आने के साथ ही घरेलू व अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा की तस्वीर भी साफ होने लगी है।

लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इसके लिए हुआ समझौता

एयरपोर्ट से 17 अप्रैल 2025 को विमान सेवा शुरू होने के पहले दिन से ही तीन अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा, 25 घरेलू और दो कार्गो सेवाएं शुरू की जाएंगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ इसके लिए अनुबंध हुआ है। दोनों एयरलाइंस सिंगापुर, दुबई और ज्यूरिख के लिए विमान सेवा पहले दिन से उपलब्ध होंगी। आइएटीए से स्वीकृति मिल चुकी है। केंद्र सरकार के स्तर पर अभी स्वीकृति मिलना शेष है। लुफ्थांसा 78 देशों के लिए 179 विमान सेवाओं का संचालन कर रही है।

घरेलू विमान सेवा के लिए इंडिगो और आकाशा एयरलाइंस से हुआ करार

घरेलू विमान सेवा के लिए इंडिगो व आकाशा एयरलाइंस से पहले ही करार हो चुका है। लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, चेन्नई, बेंगलुरु, श्रीनगर, जयपुर आदि प्रमुख शहर नोएडा एयरपोर्ट से जुड़ जाएंगे।

यूपी जेल मंत्री और डीजी ने बंदियों के साथ मनाई दीवाली, दारा सिंह चौहान ने सीएम योगी का दिया खास संदेश

परिवहन विशेष न्यूज

गाजियाबाद के डासना जिला कारागार में जेल मंत्री दारा सिंह चौहान और डीजी जेल पीवी रामशास्त्री ने बंदियों के साथ दीवाली मनाई। बंदियों को दीवाली की शुभकामनाएं देने के साथ ही बंदियों के बच्चों को दीवाली पर तोहफे दिए। जेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में दीवाली धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया था।

गाजियाबाद। जेल मंत्री दारा सिंह चौहान और डीजी जेल पीवी रामशास्त्री ने डासना जिला कारागार में बंदियों के साथ दीवाली मनाई। बंदियों को दीवाली की शुभकामनाएं देने के साथ ही बंदियों के बच्चों को दीवाली पर तोहफे दिए।

जेल मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जेलों में दीवाली धूमधाम से मनाने का संकल्प लिया था। गाजियाबाद जिला जेल को बंदियों के बनाये दिये और मोमबत्ती से ही रोशन किया गया था। उन्होंने जेल में बंदियों की आर्ट गैलरी देखकर उसकी प्रशंसा की।

एक बंदी-एक दीप कार्यक्रम का हुआ आयोजन

बृहस्पतिवार शाम जिला कारागार में एक बंदी-एक दीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर जेल आए जेल मंत्री दारा सिंह चौहान और जेल महानिदेशक पीवी रामशास्त्री जेल में बंदियों को दी जा रही सुविधाओं का हाल देखा। बंदियों के हाथ से बनाए दिये और मोमबत्ती जलाकर उन्होंने जेल में दीवाली की सभी के शुभकामनाएं दीं।

जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि जिला कारागार में आर्ट गैलरी उन्हें बहुत पसंद आई है। बंदियों की बनाई पेंटिंग भी अच्छी हैं। कारागार में सफाई व्यवस्था से भी वह संतुष्ट दिखे। जेल परिसर को दिये और मोमबत्ती से सजाया गया था। जेल में इस मौके पर रामलीला का मंचन भी किया गया।

जिसमें बंदियों ने ही सभी पात्र निभाए। जिला कारागार में बंदियों की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू की गई चौपाल व्यवस्था पर भी उन्होंने संतोष जताया। जेल में बंदियों के स्वास्थ्य, खान-पान और कानूनी अधिकारों पर भी उन्होंने लगातार काम किए जाने पर जोर दिया।

जेलों के उत्पाद बाजार में उतारे जाएंगे

जेल मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में वन जेल वन प्राडक्ट (ओजीओपी) के तहत जेलों के उत्पादों को बाजार में उतारे जाने पर योजना बनाई जा रही है। डीजी जेल इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहे हैं। हर जेल में एक उत्पाद को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है।

भाई दूज पर जेल में होगी खास व्यवस्था

भाई दूज पर जिला कारागार में दिनभर खुली मिलाई होगी। भाइयों से मिलने आने वाली बहनें बिना पर्ची बनवाये सुबह सात बजे से मिल सकती हैं। जिला कारागार में भाई दूज पर खुले में मिलने की व्यवस्था की जाएगी।

जेल मंत्री और डीजी जेल ने बंदियों के साथ दीवाली मनाकर उन्हें दीवाली की शुभकामनाएं दी हैं। जेल मे भाई दूज के मौके पर पूरे दिन खुली मिलाई होगी। बहनों को जेल में बंद भाई से मुलाकात के लिए पर्ची बनवाने की जरूरत नहीं है।

भारत के आर्थिक विकास में जनजाति समाज का है भरपूर योगदान

प्रह्लाद सबनानी

शुरुआती दौर में तो जनजाति समाज उक्त वर्णित वनस्पतियों एवं उत्पादों का उपयोग केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते रहे हैं परंतु हाल ही के समय में इन वनस्पतियों का उपयोग व्यावसायिक रूप से भी किया जाने लगा है।

भारत भूमि का एक बड़ा हिस्सा वनों एवं जंगलों से आच्छादित है। भारतीय नागरिकों को प्रकृति का यह एक अनोखा उपहार माना जा सकता है। इन वनों एवं जंगलों की देखभाल मुख्य रूप से जनजाति समाज द्वारा की जाती रही है। जनजाति समाज की विकास यात्रा अपनी भूख मिटाने एवं अपने को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से केवल वनों के इर्द गिर्द चलती रहती है। वास्तविक अर्थों में इसीलिए जनजाति समाज को धरतीपुत्र भी कहा जाता है। प्राचीन काल से केवल प्रकृति ही जनजाति समाज की सम्पत्ति मानी जाती रही है, जिसके माध्यम से उनकी सामाजिक, आर्थिक एंव पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अनादि काल से जनजाति संस्कृति व वनों का चोली दामन का साथ रहा है और जनजाति समाज का निवास क्षेत्र वन ही रहे हैं। इस संदर्भ में यह भी कहा जा सकता है कि वनों ने ही जनजातीय जीवन एंव संस्कृति के उद्भव, विकास तथा संरक्षण में अपनी आधारभूत भूमिका अदा की है। भील वनवासियों का जीवन भी वनों पर ही आश्रित रहता आया है। जनजाति समाज अपनी आजीविका के लिए वनों में उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते रहे हैं।

ब्यूटी ब्लॉगर मालविका सीतलानी के तलाक के पीछे की वजह आई सामने

भारतीय वन क्षेत्रों में पाए जाने वाले प्रमुख वनस्पतियों, पेड़ों एवं उत्पादित वस्तुओं में शामिल रहे हैं बबूल, बेर, चन्दन, धोक, धामन, धावडा, गुदी, हल्दू, इमली, जामुन, कजरी, खेजडी, खेडा, कुमटा, महुआ, नीम, पीपल, सागवान, आम, मुमटा, सालर, बानोटीया, गुलर, बांस, अरीठा, आंवला, गोंद, खेर, केलडी, कडैया, आवर, सेलाई वृक्षों से करा, कत्था, लाख, मौम, धोली व काली मुसली, शहद, आदि। इनमें से कई वनस्पतियों की तो औषधीय उपयोगिता है। कुछ जड़ी बूटियों जैसे आंवला का बीज, हेतडी, आमेदा, आक, करनीया, ब्राह्मी, बोहडा, रोंजडा, भोग पत्तियां, धतुरा बीज, हड, भुजा, कनकी बीज, मेंण, अमरा, कोली, कादां, पडूला, गीगचा, इत्यादि का उपयोग रोगों के निवारण के लिए किया जाता रहा है। आमेदा के बीजों को पीसकर खाने से दस्त बंद हो जाते हैं। अरण्डी के तेल से मालिश एंव पत्तों को गर्म करके कमर में बांधने से दर्द कम हो जाता है। बुखार को ठीक करने के लिए कड़ा वृक्ष के बीजों को पीस कर पीते हैं। जोडों में दर्द ठीक करने के लिए ग्वार व सैजने के गोंद का उपयोग करते हैं। फोडे फुन्सियों एवं चर्म रोग को ठीक करने के लिए नीम के पत्तों को उबालकर पीते हैं। इसके अलावा तुलसी, लौंग, सोठ, पीपल, काली मिर्च का उपयोग बुखार एवं जुखाम ठीक करने के लिए किया जाता है।

शुरुआती दौर में तो जनजाति समाज उक्त वर्णित वनस्पतियों एवं उत्पादों का उपयोग केवल स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही करते रहे हैं परंतु हाल ही के समय में इन वनस्पतियों का उपयोग व्यावसायिक रूप से भी किया जाने लगा है। व्यावसायिक रूप से किए जाने वाले उपयोग का लाभ जनजाति समाज को न मिलकर इसका पूरा लाभ समाज के अन्य वर्गों के लोग ले रहे हैं। उक्त वनस्पतियों एवं उत्पादों का व्यावसायिक उपयोग करने के बाद से ही प्रकृति का दोहन करने के स्थान पर शोषण किया जाने लगा है क्योंकि कई उद्योगों द्वारा उक्त उत्पादों का कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। इससे ध्यान में आता है कि जनजाति समाज द्वारा देश की अर्थव्यवस्था में विकास को गति देने के उद्देश्य से अपनी भूमिका का निर्वहन तो बहुत सफल तरीके से किया जाता रहा है परंतु अर्थव्यवस्था के विकास का लाभ जनजातियों तक सही मात्रा में पहुंच नहीं सका है।

हालांकि भारत में प्राचीन काल से ही जनजाति समाज जंगलों में अपना जीवन यापन करता रहा है और वनोपज (जैसे मध्यप्रदेश में तेन्दु पत्ता को एकत्रित करना) को एकत्रित करता रहा है परंतु अब धीरे धीरे अपने आप को यह समाज कृषि कार्य एवं पशुपालन जैसे अन्य कार्यों में भी संलग्न करने लगा है। जनजाति समाज ने बिना किसी भय के सघन वनों में जंगली जानवरों व प्राकृतिक आपदाओं से लड़ते हुए अपने जीवन को संघर्षमय बनाया है। जनजाति समाज ने कृषि कार्य के लिए सर्वप्रथम जंगलों को काटकर जलाया। भूमि साफ कर इसे कृषि योग्य बनाया और पशुपालन को प्रोत्साहन दिया। विकास की धारा में आगे बढ़ते हुए धीरे-धीरे विभिन्न गावों एवं कस्बों का निर्माण किया।

आज भी जनजाति समाज की अधिकांश जनसंख्या दुर्गम क्षेत्रों में निवास करती है। इन इलाकों में संचार माध्यमों का अभाव है। हालांकि धीरे धीरे अब सभी प्रकार की सुविधाएं इन सुदूर इलाकों में भी पहुंचाई जा रही हैं। परंतु, अभी भी जनजातीय समाज कृषि सम्बन्धी उन्नत विधियों से अनभिज्ञ है। सिंचाई साधनों का अभाव एवं उपजाऊ भूमि की कमी के कारण ये लोग परम्परागत कृषि व्यवस्था को अपनाते रहे हैं और इनकी उत्पादकता बहुत कम है।

जनजाति समाज ने वनों के सहारे अपनी संस्कृति को विकसित किया। घने जंगलों में विचरण करते हुए उन्होंने जंगली जानवरों शेर, भालु, सुअर, गेंडे, सर्प, बिच्छु आदि से बचने के लिए आखेट का सहारा लिया। वनों एवं पहाडियों के आन्तरिक भागों में रहते हुए भील समाज शिकार करके अपनी आजीविका चलाता रहा है। भील समाज जंगलों में झूम पद्धति से खेती, पशुपालन, एवं आखेट कर अपने परिवार का पालन पोषण करते रहे हैं।

घने जंगलों में जनजाति समाज को प्रकृति द्वारा, स्वछंद वातावरण, स्वच्छ जल, नदियां, नाले, झरने, पशु पक्षियों का कोलाहल, सीमित तापमान, हरियाली, आर्द्रता, समय पर वर्षा, मिटटी कटाव से रोक, आंधी एंव तूफानों से रक्षा, प्राकृतिक खाद, बाढ़ पर नियंत्रण, वन्य प्राणियों का शिकार व मनोरंजन इत्यादि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराया जाता रहा है। इसी के चलते जनजाति समाज घने जंगलों में भी बहुत संतोष एवं प्रसन्नता के साथ रहता है।

जनजाति समाज आज भी भारतीय संस्कृति का वाहक माना जाता है क्योंकि यह समाज सनातन हिंदू संस्कृति का पूरे अनुशासन के साथ पालन करता पाया जाता है। जनजाति समाज आज भी आधुनिक चमक दमक से अपने आप को बचाए हुए है। इसके विपरीत शहरों में रहने वाला समाज समय समय पर भारतीय परम्पराओं में अपनी सुविधानुसार परिवर्तन करता रहता है।

हाल ही के समय में अत्यधिक आर्थिक महत्वकांक्षा के चलते वनों का अदूरदर्शितापूर्ण ढंग से शोषण किया जा रहा है। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 110 लाख हैक्टर भूमि के वन नष्ट किये जा रहे है। पर्यावरण विशेषज्ञों के अनुसार प्रत्येक देश में उपलब्ध भूमि के लगभग 33 प्रतिशत भाग पर वन होना आवश्यक है। यदि वनों का इस प्रकार कटाव होता रहेगा तो जनजाति समाज पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है।

भारत द्वारा इस संदर्भ में कई प्रयास किए जा रहे हैं। देश में वनों के कटाव को रोकने के लिए वर्ष 2015 एवं 2017 के बीच देश में पेड़ एवं जंगल के दायरे में 8 लाख हेक्टेयर भूमि की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही, भारत ने वर्ष 2030 तक 2.10 करोड़ हेक्टेयर जमीन को उपजाऊ बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 2.60 करोड़ हेक्टेयर कर दिया है ताकि वनों के कटाव को रोका जा सके।

भारत में सम्पन्न हुई वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 8.6 प्रतिशत है। जनजाति समाज को देश के आर्थिक विकास में शामिल करने के उद्देश्य से केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि इस समाज की कठिन जीवनशैली को कुछ हद तक आसान बनाया जा सके।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV Drive the Future

कमजोर ईवी मांग के कारण दक्षिण कोरिया का कार निर्यात तीसरी तिमाही में गिरा

परिवहन विशेष न्यूज

सियोल, 31 अक्टूबर को आंकड़ों से पता चला कि विशेष रूप से यूरोप में पर्यावरण-अनुकूल कारों की कमजोर मांग के कारण 2024 की तीसरी तिमाही में दक्षिण कोरिया की यात्री कारों का निर्यात दो साल में पहली बार गिर गया।

कोरिया सीमा शुल्क सेवा के अनुसार, दक्षिण कोरियाई कार निर्माताओं ने जुलाई-सितंबर की अवधि के दौरान 13.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की यात्री कारों की शिपिंग की, जो एक साल पहले की तुलना में 4.7 प्रतिशत कम है।

समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2022 की पहली तिमाही के बाद यह पहली वार्षिक गिरावट है, जब कार निर्यात में 0.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी। दक्षिण कोरियाई वाहनों का निर्यात सालाना आधार पर 3 प्रतिशत गिरकर 590,000 इकाई रह गया।

आंकड़ों से पता चलता है कि तीसरी तिमाही में आयात 12.6 प्रतिशत बढ़कर 3.04 बिलियन डॉलर हो गया, जो 2023 की चौथी तिमाही के बाद पहली सालाना वृद्धि है।

निर्यात में गिरावट तब आई जब तीसरी तिमाही में पर्यावरण-अनुकूल कारों की विदेशी बिक्री सालाना आधार पर 1.27 प्रतिशत कम होकर 5.42 बिलियन डॉलर हो गई।

विस्तार से, इलेक्ट्रिक कारों की मांग 44.4 प्रतिशत घटकर 2 अरब डॉलर रह गई, जबकि हाइब्रिड वाहनों की बिक्री 3.01 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई।

त्योहारी मांग ने वित्त वर्ष 2025 में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री को पहुंचा दिया सर्वकालिक उच्च स्तर पर

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रीन मोबिलिटी के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती पसंद और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के स्वामित्व की कम कुल लागत के कारण देश के प्रमुख मेट्रो शहरों के साथ-साथ टियर-2 और टियर-3 बाजारों में ई-टू-व्हीलर की मांग बढ़ रही है। इसके परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार इस वित्तीय वर्ष में अपने उच्चतम बिक्री स्तर पर पहुंच गया है।

भारत के शीर्ष इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता ओला इलेक्ट्रिक के साथ सबसे आगे हैं और दूसरे स्थान पर टीवीएस मोटर्स और उसके बाद बजाज ऑटो हैं। वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार 28 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की कुल बिक्री 1,09,643 यूनिट तक पहुंच गई है। दिवाली, धनतेरस और नवरात्रि के साथ-साथ अक्टूबर में बिक्री ने जुलाई में बनाए गए 1,07,612 यूनिट के पिछले रिकॉर्ड को पार कर लिया है।

विश्लेषकों का अनुमान है कि बिक्री बढ़कर 1,15,000 इकाई हो जाएगी, जो कि सितम्बर में बेची गई 88,156 इकाइयों से उल्लेखनीय वृद्धि है तथा कुल ईवी बिक्री पिछले महीने की तुलना में 30-35% अधिक होगी।

लास्ट-माइल डिलीवरी स्टार्टअप मोटरवे मोबिलिटी के संस्थापक डॉ. श्याम मोहन ने कहा, ₹हालांकि यह आंकड़ा पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च 2024 में बेचे गए 1,36,560 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रिकॉर्ड से कम है, फिर भी यह एक मजबूत बाजार प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि आने वाले दिनों के भीतर बिक्री आसानी से लगभग 1,15,000 इकाइयों तक पहुंच सकती है।₹

सेवा वितरण मुद्दों पर आलोचना और सोशल मीडिया पर आलोचना के बावजूद, बाजार की अग्रणी कंपनी ओला इलेक्ट्रिक ने 32,836 इकाइयों की बिक्री की सूचना दी, जो पिछले महीने की 25,000 इकाइयों से लगभग 30% अधिक है। कंपनी के सूत्रों के अनुसार चल रहे विवाद ने ब्रांड में उपभोक्ता विश्वास को कम नहीं किया है, बल्कि मजबूत बना हुआ है।

कंपनी ने कहा कि यह गति पूरे त्योहारी सीजन और नये साल तक जारी रहने की उम्मीद है।

इसके अलावा कई ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों पर कई इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीद के लिए उपलब्ध होने और फ्लिपकार्ट जैसे प्रमुख ब्रांडों की ओर से महत्वपूर्ण त्योहारी प्रमोशन के कारण बिक्री में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

28 अक्टूबर को वाहन के आंकड़ों के अनुसार, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो दोनों इस महीने बिक्री रिकॉर्ड स्थापित करने की राह पर हैं। टीवीएस वर्तमान में दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता है और उसने लगभग 23,867 इकाइयां बेची हैं।

30 अक्टूबर के वाहन डेटा के अनुसार, एथर एनर्जी ने अक्टूबर में अपने अब तक के सबसे अधिक मासिक डिस्पैच दर्ज किए, जिसमें देश भर में 20,000 से अधिक स्कूटर भेजे गए। यह वृद्धि एथर के सितंबर के खुदरा प्रदर्शन के बाद है, जब 12,828 वाहन बेचे गए थे।

यह एथर को अब तक की सबसे बड़ी मासिक बिक्री का स्थान दिलाता है। कंपनी के नए लॉन्च किए गए पारिवारिक स्कूटर, रिज्टा ने इस महीने की कुल बिक्री का लगभग 60%-70% हिस्सा लिया।

एथर एनर्जी ने पिछले अक्टूबर से बिक्री में 141.8% की वार्षिक वृद्धि का अनुभव किया और 31 अक्टूबर तक यह संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।

वाहन के आंकड़ों के अनुसार त्योहारी उछाल से हीरो मोटोकॉर्प और ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जैसी अन्य इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माताओं को भी फायदा हुआ है, जिनकी बिक्री में काफी वृद्धि हुई है।

बेरोजगार युवाओं ने ई-रिक्शा धोखाधड़ी में गंवाई अपनी बचत

परिवहन विशेष न्यूज

Wednesday 30 - October-2024 • 20th Year of Publication

Kashmir Age

"Truth we say...come what may"

Unemployed Youth Lose Savings in E-Rickshaw Fraud

Unemployed Youth

suggests that EF EV Charging Solutions is preparing to grant dealership rights to another individual without addressing the unresolved issues with D2D Enterprises. The lack of repairs or attempts to rectify the defective e-rickshaws has only added to the sense of betrayal felt by the victims.

The community is calling for large-scale action against EF EV Charging Solutions, labeling the situation as a blatant act of fraud that must not go unpunished. As the story unfolds, the hope is that justice will prevail for those who sought opportunity but found only disappointment.

बड़ी संख्या में युवा जो ई-रिक्शा को रोजगार का एक अच्छा स्रोत मानते थे, वे आर्थिक रूप से तबाह हो गए हैं, क्योंकि ईएफ ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, सोनीपत द्वारा कथित धोखाधड़ी के कारण उन्हें अपनी मेहनत की कमाई गंवानी पड़ी है।

घटनाक्रम में एक चिंताजनक मोड़ यह आया है कि जिस कंपनी ने कश्मीर में इलेक्ट्रिक रिक्शा बेचने के लिए डी2डी एंटरप्राइजेज को डीलरशिप अधिकार दिए थे, वह बिक्री के बाद आवश्यक सेवाएं प्रदान करने में विफल रहने के कारण जांच के दायरे में आ गई है।

हां, चूंकि सरकार बेरोजगारी के समाधान के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ईएफ ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस जैसी कुछ कंपनियां नौकरी पाने के इच्छुक कमजोर युवाओं का शोषण कर रही हैं।

स्थानीय युवाओं ने रोजगार की संभावना और आय के नए स्रोत के वादे से आकर्षित होकर इस पहल में भारी निवेश किया। हालांकि, कई लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा क्योंकि खरीद के तुरंत बाद ई-रिक्शा में खामियां सामने आने लगीं। जब मालिकों ने सहायता के लिए कंपनी से संपर्क किया, तो उन्हें प्रभावी सहायता नहीं मिली।

दुखद बात यह है कि इन युवा उद्यमियों, जिनमें से कई ने अपने निवेश के लिए ऋण लिया था, ने न केवल अपनी बचत खो दी है, बल्कि बढ़ते कर्ज की संभावना का भी सामना किया है। जैसे-जैसे निराशा बढ़ती गई प्रभावित व्यक्तियों ने न्याय और जवाबदेही की मांग करते हुए उपभोक्ता न्यायालय में कई शिकायतें दर्ज कीं।

कश्मीर ऐज मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि स्थानीय डीलरशिप ने इस व्यवसायिक उद्यम में महत्वपूर्ण संसाधनों का निवेश किया है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता और प्रतिष्ठा दोनों ही दांव पर लग गई है। फिर भी ईएफ ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस ने कथित तौर पर इन व्यक्तियों की दुर्दशा के प्रति बहुत कम चिंता दिखाई है।

हाल ही में एक घटनाक्रम में प्रभावित पक्षों ने परिवहन आयुक्त सचिव के समक्ष औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कंपनी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। उनका आरोप है कि कंपनी ने उन्हें धोखा दिया है, जिससे वे इस व्यवसाय के माध्यम से आजीविका सुरक्षित करने के प्रयासों के बावजूद गंभीर संकट में फंस गए हैं।

इसके अलावा, चौंकाने वाली नई जानकारी से पता चलता है कि ईएफ ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस डी2डी एंटरप्राइजेज के साथ अनसुलझे मुद्दों को संबोधित किए बिना किसी अन्य व्यक्ति को डीलरशिप अधिकार देने की तैयारी कर रहा है। दोषपूर्ण ई-रिक्शा को ठीक करने के लिए मरम्मत या प्रयासों की कमी ने पीड़ितों द्वारा महसूस किए गए विश्वासघात की भावना को और बढ़ा दिया है।

समुदाय ईएफ ईवी चार्जिंग सॉल्यूशंस के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की मांग कर रहा है, इस स्थिति को धोखाधड़ी का एक स्पष्ट कृत्य करार देते हुए, जिसे दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे कहानी सामने आती है, उम्मीद है कि उन लोगों के लिए न्याय होगा जिन्होंने अवसर की तलाश की लेकिन केवल निराशा ही मिली।

मध्य प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल पर नई सब्सिडी करने वाली घोषित, छूट के लिए ड्राफ्ट तैयार, पेट्रोल-डीजल और सीएनजी वाहन खरीदना हो जाएगा मुश्किल

परिवहन विशेष न्यूज

इलेक्ट्रिक कारें सस्ती और पेट्रोल-डीजल की कारें जल्द ही महंगी हो सकती हैं। सीएनजी से चलने वाले वाहन भी पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों की तरह महंगे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट देने के लिए ड्राफ्ट तैयार करा लिया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार पेट्रोल-डीजल और सीएनजी से चलने वाले वाहनों पर सरकार उप कर (सेस) लगाने जा रही है।

नगरीय विकास और आवास विभाग ने ये ड्राफ्ट तैयार किया है। विभाग के मंत्री और सरकार को अप्रूवल के लिए भेजा है। फिलहाल जो पॉलिसी लागू है, वह 2019 में पांच साल के लिए बनाई गई थी और यह तय किया गया था कि नई नीति लागू होने तक यह प्रभावी रहेगी। विभाग के मंत्री और वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा।

ड्राफ्ट में कहा गया है कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, उन्हें सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी फाइनल न होने के कारण सब्सिडी के स्लैब को गोपनीय रखा जा रहा है, लेकिन यह तय किया जा रहा है कि दो-पहिया, तीन-पहिया, चार-पहिया और बस-ट्रक जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद पर शुरुआती सब्सिडी दी जाएगी, जो 25 प्रतिशत तक हो सकती है। इसके लिए स्लैब तय किए जाएंगे और शुरुआती पांच हजार वाहनों पर यह सब्सिडी मिल सकती है। बाद में इसे अपग्रेड किया जाएगा।

सरकार के सामने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों के लिए वाहन चार्जिंग की सुविधा दिलाना एक बड़ी चुनौती है, इसलिए पॉलिसी ड्राफ्ट में प्रावधान किया गया है कि किस तरह से किन जगहों पर चार्जिंग स्टेशन बनाएं जाएंगे।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए हर जिले और नगरीय निकाय में लैंडबैंक भी तैयार किए जाएंगे। इन स्थानों पर 33 केवी लाइन डाली जाएगी, ताकि वाहनों की तेजी से चार्जिंग हो सके। नगरीय निकायों से जमीन की तलाश करने के लिए कहा गया है ताकि पॉलिसी मंजूर होते ही काम शुरू हो सके।

33 केवी लाइन डालने और सब स्टेशन बनाने के लिए नगरीय विकास विभाग ने विद्युत वितरण

कंपनियों को भी इस कार्यक्रम से जोड़ा है ताकि सरकार की प्राथमिकता तय होने पर इस काम में तेजी लाई जा सके।

प्रस्तावित पॉलिसी में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने और पेट्रोल-डीजल वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए टैक्स भी सेस के रूप में लगाया जा सकता है। यह टैक्स उन वाहनों पर लगेगा जो पेट्रोल-डीजल से चलते हैं ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने की प्लानिंग करें।

इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए एक पोर्टल भी तैयार किया गया है, जिसमें बताया जाएगा कि अलग-अलग रूट्स पर कहां-कहां ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं, किस चार्जिंग स्टेशन पर वाहन चार्ज हो रहे हैं और कौन से स्टेशन खाली हैं। इसमें यह तुलनात्मक जानकारी भी होगी कि पेट्रोल-डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के बीच दूरी और समय का अंतर क्या है। साथ ही इसके खर्च के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।

पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक नहीं हैं। इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने होंगे ताकि लोगों को बताया जा सके कि इन वाहनों में यात्रा सस्ती और प्रदूषण रहित होगी। इनके आग लगने जैसी घटनाओं के बारे में गलतफहमी को भी दूर किया जाएगा।

भोपाल ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के आशीष पांडेय ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अब तक इस तरह के वाहनों में पर्याप्त छूट नहीं दिए जाने से लोगों का रुझान ऐसी गाड़ियां खरीदने में कम है। भोपाल में फिलहाल दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की 8 से 10 प्रतिशत तक है। चार पहिया वाहनों का फिगर और कमजोर है। यह एक से डेढ़ प्रतिशत है।

एमपी में अभी हाइब्रिड वाहनों की ज्यादा डिमांड है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर सभी तरह के टैक्स से छूट दी है और अन्य पड़ोसी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और गुजरात ने भी कुछ हद तक छूट देने का काम किया है। इसी तरह एमपी की सरकार को चाहिए कि ऐसे वाहनों की खरीदी पर टैक्स में छूट दें और सब्सिडी भी दें। ऐसा हुआ तो इसमें सुधार आएगा।

वरेण्यम मोटर्स के संचालक और टाटा कंपनी के डीलर अवनीश राय और उनके सहयोगी अखिल बताते हैं कि अगर आप अपने पर्यावरण से प्यार करते हैं तो बहुत जल्दी ईवी गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए। लोगों से अपील है कि शोरूम में जाकर एक बार टेस्ट ड्राइव जरूर लें। अकेले टाटा की करीब 150 ईवी गाड़ियां दीपावली पर बिक रही हैं और अन्य सभी कंपनियों की मिलाकर सात सौ से अधिक ईवी कारें अगले चार दिन में बिकने वाली हैं।

मारुति ईवीएक्स का उत्पादन संस्करण 4 नवंबर को होगा प्रदर्शित

परिवहन विशेष न्यूज

मारुति की बहुप्रतीक्षित ईवीएक्स का अंतिम उत्पादन-विशिष्ट संस्करण 4 नवंबर को इटली के मिलान में अपनी वैश्विक शुरुआत करेगा। यह मूल कंपनी सुजुकी के लिए एक वैश्विक उत्पाद के रूप में ईवीएक्स के महत्व को रेखांकित करता है, क्योंकि भारत में निर्मित ईवी के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यूरोप और जापान को निर्यात के लिए चिह्नित किया गया है।

मारुति ईवीएक्स का उत्पादन सुजुकी के गुजरात प्लांट में किया जाएगा और उत्पादन की शुरुआत (एसओपी) मार्च 2025 में निर्धारित है। ईवीएक्स के मिलान डेब्यू के पीछे का कारण, जो स्थानीय यूरोपीय प्रेस और डीलरों के लिए है, यह है कि ई-एसयूवी एक वैश्विक उत्पाद है। वास्तव में पहले वर्ष के लिए उत्पादन लक्ष्य 1.4 लाख यूनिट है, जिसमें से 50 प्रतिशत निर्यात के लिए निर्धारित किया गया है।

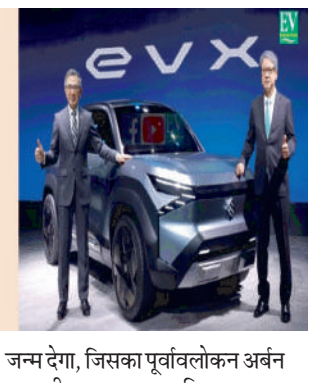

भारतीय दर्शकों को प्रोडक्शन-स्पेक ईवीएक्स को देखने के लिए 17-22 जनवरी तक आयोजित होने वाले भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 तक इंतजार करना होगा। हमारा पहला बाजार होगा जहां ईवी की कीमत की घोषणा की जाएगी। अब भारत में लॉन्च होने के दो महीने बाद लॉन्च होने की उम्मीद है। इसके बाद ईवीएक्स को चुनिंदा यूरोपीय बाजारों में पेश किया जाएगा, उसके बाद जापान में।

मार्च 2025 में आने पर मारुति ईवीएक्स का उत्पादन संस्करण हाल ही में लॉन्च की गई टाटा कर्व ईवी (17.49 लाख-21.99 लाख रुपये) और आगामी हुंडई क्रेटा ईवी को टक्कर देगा। यह टोयोटा के ईवीएक्स के व्युत्पन्न को भी जन्म देगा, जिसका पूर्वावलोकन अर्बन एसयूवी अवधारणा द्वारा किया गया था। यह ई-एसयूवी भी अगले साल मार्च में सुजुकी के गुजरात प्लांट में उत्पादन में जाने वाली है। कीमत की घोषणा साल के अंत में होने की उम्मीद है।

उम्मीद है कि दोनों ईवी में एक ही बैटरी पैक विकल्प (48kWh और 60kWh यूनिट की उम्मीद है) के साथ-साथ ई-मोटर्स भी होंगे। मारुति ने अभी तक पुष्टि नहीं की है कि प्रोडक्शन-स्पेक ईवीएक्स में AWD क्षमता होगी या नहीं, जिसके बारे में कहा जाता है कि टोयोटा के वर्जन में यह खूबी है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर को खरीदने की मची लूट

परिवहन विशेष न्यूज

शेयर बाजार में गुरुवार, 31 अक्टूबर को बड़ी गिरावट के बीच इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयरों को खरीदने की होड़ मच गई। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शेयर में 105.80 रुपये के पिछले बंद भाव के मुकाबले 5 फीसदी की तेजी आई। कारोबार के दौरान शेयर 111.05 रुपये पर पहुंच गया। दिसंबर 2023 में शेयर का भाव 143.80 रुपये पर पहुंच गया। यह शेयर का 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है। नवंबर 2023 में शेयर 46.10 रुपये के 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर था। बता दें कि पिछले पांच सालों में यह शेयर 31,000 फीसदी चढ़ चुका है। इस दौरान इसका भाव 35 पैसे से बढ़कर 111.05 रुपये पर पहुंच गया है।

मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 62.10 फीसदी हिस्सेदारी प्रमोटर के पास है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डर्स के पास 37.90 फीसदी हिस्सेदारी है। इसके प्रमोटरों में कविता जयेशभाई ठक्कर, आरतीबेन जयेशभाई ठक्कर शामिल हैं। इसके अलावा

प्रमोटर समूह में श्री साईबाबा एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड, रघुवीर इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।

हाल ही में मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड ने पश्चिम बंगाल में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए हाईटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड में 70 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। इस कदम से मर्करी को हाईटेक के मौजूदा परिचालन, वितरण नेटवर्क और ग्राहक आधार का लाभ उठाने में मदद मिलेगी, जिससे बाजार हिस्सेदारी बढ़ेगी और मुनाफे में सुधार होगा यह अधिग्रहण नकद लेनदेन है। इसमें हाईटेक के 70 प्रतिशत इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया गया है। अगस्त 2022 में अस्तित्व में आई कंपनी- हाईटेक ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रिक 3W वाहनों के निर्माण में माहिर है

मर्करी ईवी-टेक लिमिटेड को पहले मर्करी मेटल्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह कंपनी भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक विंटेज कार, इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट और इलेक्ट्रिक वाहन के निर्माण में शामिल है।

पाठ्यक्रम में जुड़ने से युवाओं को लाभ

विजय गर्ग

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, भारत में दो में से एक स्नातक रोजगार के योग्य नहीं है यानी भारत में केवल 51 प्रतिशत स्नातक ही रोजगार के लिए तैयार हैं। यह आंकड़ा इस बात पर जोर देता है कि छात्रों को केवल सैद्धांतिक शिक्षा से नहीं, बल्कि व्यावहारिक अनुभव के साथ तैयार करने की आवश्यकता है। यूजीसी का यह निर्णय छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम है। नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 में इंटर्नशिप के महत्व पर जोर दिया गया है। यूजीसी के अनुसार, तीन वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम में चौथे सेमेस्टर के बाद 60 से 120 घंटे की इंटर्नशिप अनिवार्य होगी, जबकि चार वर्षीय आनर्स और रिसर्च कोर्स में चौथे और आठवें सेमेस्टर के बाद इंटर्नशिप करनी होगी। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों की वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से अवगत कराना है। गौरतलब है कि भारत के स्किल इंडिया मिशन के तहत अब तक 1.25 करोड़ से अधिक युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि, इनमें से केवल 50 प्रतिशत युवाओं को रोजगार मिल पाया, जो बताता है कि प्रशिक्षण के बावजूद रोजगार की कमी और अर्ध कुशल श्रमिकों की श्रम बाजार में सीमित मांग है।

सरकारी प्रयास बदलते आर्थिक परिदृश्य में सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा अप्रेंटिसशिप के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं ताकि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा सके और उद्योगों की बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम की नींव 1961 में अप्रेंटिसशिप एक्ट के माध्यम से रखी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक प्रशिक्षण और कुशल श्रमिकों की पूर्ति करना था। हालांकि, कई वर्षों तक इस कार्यक्रम का विकास धीमा रहा और अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो सके। वर्ष 2014 के बाद से सरकार ने इस दिशा में ठोस कदम उठाए, जिसमें अप्रेंटिसशिप नियमों को अधिक लचीला और उद्योगों के अनुकूल बनाया गया।

वर्ष 2015 में शुरू किए गए 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की गई। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम को 2016 में शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत उद्योगों को अप्रेंटिसशिप के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं। इस योजना के तहत नियोक्ताओं को प्रशिक्षण के लिए सरकार से सब्सिडी मिलती है, जिससे उनकी अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण की लागत कम हो जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र में अप्रेंटिसशिप को रोजगार देने का एक सशक्त माध्यम माना जाता है। सरकार और उद्योग संगठनों के बीच आपसी सहयोग से अप्रेंटिसशिप की संख्या और गुणवत्ता में सुधार हुआ है 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने अप्रेंटिसशिप के महत्व को और भी बढ़ाया है, खासकर विनिर्माण, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में सीआइआइ (कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री) और फिक्की (फेडरेशन आफ इंडियन चैंबर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री) जैसे उद्योग संगठनों ने भी अप्रेंटिसशिप के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योगों के भीतर कुशल मानव संसाधन तैयार करने और रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से ये संगठनों ने प्रशिक्षण और कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित किया है।

नियोक्ताओं से समन्वय डिजिटल

क्रांति के दौर में अप्रेंटिसशिप भी आधुनिक तकनीकों के साथ कदमताल कर रही है। डीजी- शिप जैसे पोर्टल के माध्यम से अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण और संचालन को आसान बनाया गया है। सब ही, कई आनलाइन प्लेटफार्म और एस के जरिए युवाओं को अप्रेंटिसशिप के अवसरों की जानकारी दी जा रही है। सरकार ने अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल लांच किया है, जो नियोक्ताओं और अप्रेंटिस के बीच सेतु का कार्य करता है। इस प्लेटफार्म के जरिए अप्रेंटिस अपने क्षेत्र के अनुसार प्रशिक्षकों और उद्योगों के साथ जुड़ सकते हैं। इस डिजिटल पहल से पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो रही है।

चुनौतियां भारत में अप्रेंटिसशिप के प्रसार में अभी भी कई चुनौतियाँ हैं। भारत में अप्रेंटिसशिप / प्रशिक्षुता कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी सीमित है। अधिकांश उद्योग, विशेषकर छोटे और मध्यम आकार के उद्योग, अप्रेंटिस/ प्रशिक्षु रखने से कतराते हैं। इसका कारण बुनियादी ढांचे की कमी, संसाधनों की अनिश्चितता और अतिरिक्त प्रशासनिक जिम्मेदारियों का डर है। इसके अलावा, कई उद्योग यह नहीं समझते कि अप्रेंटिसशिप उनके दीर्घकालिक लाभ में कैसे योगदान दे सकती है। अप्रेंटिसशिप का उद्देश्य युवाओं को व्यावहारिक और आधुनिक कौशल प्रदान करना है। लेकिन भारत में प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर प्रश्नचिन्ह हैं। कई अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम केवल औपचारिकता के रूप में चलते हैं, जहां प्रशिक्षुओं को उचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन नहीं मिलता। सुविधाओं का विस्तार आम तौर पर हमारे देश के शैक्षणिक संस्थानों में अप्रेंटिसशिप को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे यह धारणा बनती है कि यह केवल एक वैकल्पिक रास्ता है, न कि मुख्यधारा का करियर विकल्प। अप्रेंटिस को मिलने वाला मानदेय भी अक्सर बहुत कम होता है, जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में विफल रहता है। उन्हें अन्य लाभ जैसे बीमा, पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाएं नहीं मिलती हैं। इस कारण अप्रेंटिस कार्यक्रमों के प्रति युवाओं का आकर्षण कम हो जाता है। सभी पक्षों को समझना होगा कि युवाओं की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें मानदेय दिया ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं होने के कारण ही अप्रेंटिसशिप के प्रति अच्छी धारणा नहीं बन पाई है।

प्रणाली में सुधार के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। उद्योग और शिक्षण संस्थानों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई जाने वाली सामग्री वास्तविक कार्यस्थल की आवश्यकताओं में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जागरूकता अभियानों की शुरुआत की जानी चाहिए, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि यह करियर विकास का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। सरकार की यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अप्रेंटिसें मिले, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त ही सकें। इसके साथ ही, छोटे और मध्यम उद्योगों को अप्रेंटिसशिप को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसमें नीतिगत सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहनों का विशेष ध्यान रखा जाए।

संपादकीय

राम वाली दिवाली

दीपावली तो राम वाली ही होती है, लेकिन इस बार की दिवाली कई मायनों में अद्भुत, अनुपम, अभूतपूर्व रही। जिन प्रभु श्रीराम के सम्मान में हम दिवाली मनाते रहे हैं, उनकी जन्मभूमि, कर्मभूमि अयोध्या ऐसी जगमगाई, जो कमोबेश अकल्पनीय लगी। प्रभु के भव्य मंदिर बनने और उसमें विराजमान होने के बाद यह प्रथम दीपावली थी। रामभक्तों और इस देश के नागरिकों ने 500 साल तक सांस्कृतिक पीड़ा झेली, भगवान राम तक अपमानित होते रहे, आस्था और सांस्कृतिक विरासत के लिए न जाने कितने संघर्ष करने पड़े, प्राणों की आहुति तक देनी पड़ी। किसी भी देश की सांस्कृतिक स्वतंत्रता उसकी राजनीतिक, भौगोलिक आजादी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यह देश ने अयोध्या राम मंदिर के संदर्भ में महसूस किया होगा! इस साल दीपोत्सव के दिन अयोध्या की सरयू नदी के घाटों पर 25 लाख से अधिक दीये प्रज्वलित किए गए। राम मंदिर परिसर में भी एक लाख दीये रोशन किए गए। सरयू के तट पर ही 1121 आस्थावान चेहरों ने, एक साथ महाआरती गाई और प्रभु राम के प्रति भक्ति-श्रद्धा की भावाभिव्यक्ति की। बेशक एक बार फिर अयोध्या ने 'गिनीज बुक का विश्व-कीर्तिमान' स्थापित किया, लेकिन अयोध्या के जरिए यह सांस्कृतिक जागरण की एक उजालामयी भोर उगी। अंधेरे, निराशा, दुष्प्रचार और सांप्रदायिक विरोध गायक हुए। इस बार अयोध्या के जरिए दीपावली आपसी समभाव, सौहार्द और सकारात्मकता का पर्व साबित हुई, क्योंकि हिंदुओं से भी इतर कइयों ने 'राम की दिवाली' मनाई। कुछ सनातन-विरोधी शैतान भी हैं, जिनका जिक्र उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में किया, लेकिन भाषा और तेवर 'दिवाली' के दिन ऐसे नहीं होने चाहिए थे।

अयोध्या और राम के भक्त उन्हें दंडित जरूर करेंगे। अलबत्ता अयोध्या को कुछ और साबित नहीं करना है। यदि योगी ने वोट और राजनीति के संदर्भ में कहा है कि अब अयोध्या को साबित करना है, तो वह एक महानतम लक्ष्य का बौनापन है। राम मंदिर महज वोट या चुनाव जीतने की खातिर नहीं बनवाया गया। यह हिंदुओं की आस्था का संकल्प था और गुलामी से आजाद कराया जाना था। उसमें निर्णायक भूमिका सर्वोच्च अदालत के पांच न्यायाधीशों ने निभाई। बहरहाल हम सनातन-विरोधी शैतानों को भी माफ करने के पक्षधर हैं, क्योंकि यह पूरी तरह 'राम की दिवाली' थी और प्रभु की सीख भी यही है। अयोध्या और 'जय श्रीराम' के उद्घोष सरहद पर मौजूद सैनिकों ने भी किए और दीप-पर्व मनाया। यह खबर भी दीपोत्सव के मौके पर ही आई कि पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत-चीन की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। अस्थायी निर्माण और तंबू वगैरह ध्वस्त किए जा चुके हैं। साझा गश्त की संभावनाएं बन रही हैं। अप्रैल, 2020 की स्थिति बहाल होने को है। पूर्वाग्रही विपक्षी अब भी सवाल और संदेह करेंगे, यह उनकी फितरत है। अतीत बड़ा सवालिया है। उसे फिलहाल भूलना ही बेहतर है। दोनों पक्षों के सैनिकों ने, 'राम वाली दिवाली' के उपलक्ष्य में, मिठाई के डिब्बों का आदान-प्रदान किया। एक द्विपक्षीय समझौता सार्थक और साकार होता लग रहा है। यह धोखेबाजी वाली दोस्ती या संबंध नहीं है। सैन्य कमांडर और राजनयिक अब भी साझा वार्तालाप करते रहेंगे। विवादों की गुत्थियां सुलझाएंगे, लेकिन हमारे सैनिकों की पैनी निगाहें चीनी सैनिकों की सक्रियता पर चिपकी रहेंगी। दीप-पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के कच्छ बॉर्डर पर गए और सैनिकों को लड्डू खिला कर दीपावली मनाई। यह भारत की संचित ताकत और क्षमता का ही परिणाम है कि दुनिया उसकी सांस्कृतिक विरासत में भी भागीदार बनना चाहती है।

पहाड़ी दिवस कितना हिमाचली

एक ढर्रा मापते हुए फिर 'पहाड़ी दिवस', कुछ कविताएं, कुछ भाषण और राहत की सांस लेता साहित्य जगत। कम से कम आज तक यह पहाड़ी दिवस न हिमाचली दिवस हो सका और न ही हिमाचलियों का स्वाभिमान बन सका। आश्चर्य यह कि इस दौरान कला, भाषा, संस्कृति, तीज-त्योहार और विभिन्न इवेंट्स का बाजार हिमाचल तक पहुंच गया, लेकिन हम अपने पहाड़ीपन को कहीं बहुत दूर छोड़ आए। एक नवंबर नामक सिक्के के एक पहलू में दुम दबाए हिमाचल आज पहाड़ी के नाम पर चंद कवियों को मेहनताना दे देगा या पहाड़ी की दिहाड़ी में हमारा कला, भाषा एवं संस्कृति विभाग या संबंधित अकादमी अपने होने का कर्ज उतार देगी, वरना मैं कौन और तू कौन के बीच न पहाड़ी माहौल बचा और न ही हिमाचलियत का शृंगार हुआ। अलबत्ता यही कवि महोदय भाषाई विद्वेष के सिद्ध पुरुष बन 'हिमाचली भाषा' की प्रस्तावना मात्र से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तब इन्हें विशिष्ट संस्कृति के तालाब नजर आते हैं, लेकिन गुम होते भाषाई सरोकारों के बीच चुल्लू भर पानी दिखाई नहीं देता। पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों का 'आन मिलो सजना' अभियान एक ऐसी हकीकत है जो हिमाचल को भाषाई ताकत व लिखने को एक सशक्त कलम सौंपती है, लेकिन हिमाचली भाषा के नाम पर सर्दी-जुकाम हो जाता है। पंजाब में रहते हुए आधुनिक हिमाचल में शामिल हुए कांगड़ा के पर्वतीय इलाके आज के ऊना, हमीरपुर, कुल्लू व लाहुल-स्पीति एवं नालागढ़ क्षेत्र ही नहीं थे, बल्कि वहां सांस्कृतिक संरक्षण की कोई मिलावट नहीं थी। चंडीगढ़ के रोज गार्डन के सांस्कृतिक मंच पर पंजाब की विशालता में भाषाई स्तंभ की आज भी अगर एक दिशा पंजाबी को इंगित करती है, तो दो अन्य पर हरियाणवी और कांगड़ी बोली के संदर्भ उकेरे गए हैं। उस दौर में आकाशवाणी जालंधर नियमित रूप से 'पर्वत की गूंज' कार्यक्रम के तहत सांस्कृतिक छांव का पहरुआ बना रहता था। ऐसे में पंजाब के जिस हिस्से ने हिमाचल की विशालता को जन्म दिया, उसके भाषाई सरोकारों को रोकने के लिए सियासी पि ू तैयार हो गए, क्योंकि हिमाचली भाषा की प्रासंगिकता और उत्पत्ति की वजह पंजाब पुनर्गठन रहा है। आश्चर्य यह कि जब पंजाबी बोलियों को पंजाबी भाषा का स्वरूप और मान्यता का शृंगार दिया जा रहा था, तो इसमें हिमाचल की आठ बोलियां भी समाहित हुईं और ये ओल्ड हिमाचल के बिलासपुर, मंडी और चंबा जिलों से भी ताल्लुक रखती हैं।

हम अगर 'जम्मू की राह से चंबा की दूरी' मापते रहे हैं, तो मानव इतिहास की परंपराओं में अभिव्यक्ति का यथार्थ सांस्कृतिक जड़ें रही हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिमाचल की परिधि में सिमटती विचारधारा ने जम्मू की राह के बजाय शिमला की राह पर, परंपरा और संस्कृति से पारंपरिक गीत को जोड़ दिया। बेशक हिमाचल की भाषाई एकरूपता और समझ को बढ़ाते हुए, लोक गायकों ने साबित कर दिया कि हमारी साझी विरासत में 'हिमाचली भाषा' को किस तरह व किस रूप में अंगीकार करना होगा। अगर कुलदीप शर्मा अब 'बडियों को तुडक़ा लगाकर' हिमाचली भाषा का सांस्कृतिक परिदृश्य एक कर रहे हैं तो प्रदेश के साहित्य में भौगोलिक सामंजस्य, पृष्ठभूमि, अध्ययन, सरोकार व शब्दावली को एक करने का माद्दा होना चाहिए। यह समय की चुनौती भी है और इसका सबसे बड़ा राजनीतिक उदाहरण पाकिस्तान के पंजाब में मिलता है जहां राष्ट्रभाषा के नाम पर पंजाबी भाषा को अछूत बना दिया गया। वहां की विरासत धीरे-धीरे शिक्षा के नाम पर उर्दू की चाकरी करते हुए पंजाबी को सिर्फ पुरानी पीढ़ी की बोलचाल तक महदूद कर चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान में पंजाबी अब पढ़ाई नहीं जाती। हम हिमाचल में अपने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी के भाषाई चाबुक से हांक कर भले ही नौकरी के काबिल बना दें, लेकिन पाठ्यक्रम में अगर 'हिमाचली भाषा' नहीं जोड़ी, तो एक दिन मातृ बोली भी अतीत हो जाएगी। कम से कम सांस्कृतिक समारोहों की वरीयता में संसाधनों का आबंटन तो बता ही रहा है कि दुनिया अब किसी और मुहाने पर खड़ी है। कांगड़ा वैली कार्निवाल में अगर करनैल राणा का सम्मान नहीं है और पंजाब से निकले सतिंद्र सिंह सरताज जैसे गायक को एकमुश्त तेईस लाख मिल रहे हैं, तो वहां आए मुख्यातिथियों ने लाल कालीन के नीचे कहीं हिमाचली भाषा की गर्दन पर पांव जरूर रख दिया है।

विदेश में पढ़ाई का रास्ता खोलेंगे ये टेस्ट

विजय गर्ग

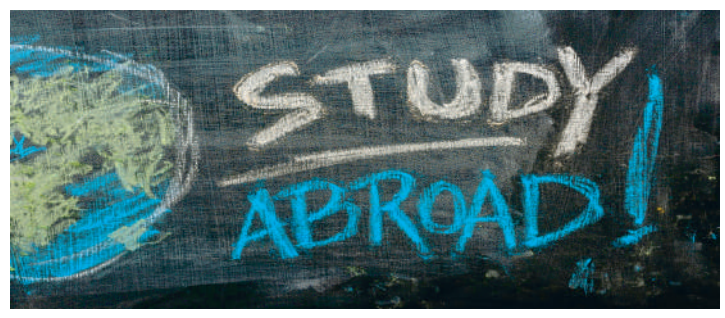

ऑनलाइन ग्लोबल शिक्षा के इस दौर में भी प्रतिष्ठित विदेश यूनिवर्सिटी में ऑफलाइन पढ़ाई करने का महत्व कम नहीं हुआ है। बीते साल विदेश से पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 8 लाख से ज्यादा रही। वहीं इंडियन स्टूडेंट मोबिलिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2025 तक विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या बीस लाख के आसपास पहुंच जाएगी। ऐसा इसलिए भी कि ऑफलाइन आप सिर्फ वहां की बेहतर शिक्षा का हिस्सा ही नहीं बनते, उन विश्वविद्यालयों की संस्कृति का हिस्सा बनकर अपना चहुंमुखी विकास करने का मौका भी मिलता है, जिससे ग्लोबल प्रतियोगिता के दौर में आपके पास सॉफ्ट स्किल्स भी विश्व स्तरीय होते हैं। साथ ही पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेश में नौकरी का मौका मिलना भी एक बड़ा आकर्षण है। भारतीय युवाओं पढ़ाई के लिए लोकप्रिय देशों में अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आज हम बताएंगे विदेश में पढ़ाई के लिए जरूरी योग्यता परीक्षाओं के बारे में।

अंग्रेजी का टेस्ट है पहला कदम

अगर आप अपनी पढ़ाई विदेशी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, तो सबसे पहली शर्त तो अंग्रेजी में प्रवीणता ही है। इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम (IELTS), टेस्ट ऑफ इंग्लिश ऐज ए फरिन लैंग्वेज यानी टोफिल (TOEFL), डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट (DET), इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी पीटीई (PTE) और कैमब्रिज इंग्लिश एडवांस्ड (CI एडवांस्ड) इसकी कुछ प्रमुख परीक्षाएं हैं। ये अंग्रेजी भाषा में आपकी योग्यता का आकलन करती हैं। आइए इनके बारे में जानें:

आईईएलटीएस इस टेस्ट्स की मान्यता 140 से अधिक देशों के लगभग 12,000 संस्थानों में है। इसमें आपकी अंग्रेजी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग का टेस्ट होता है। इसमें भी दो मॉड्यूल होते हैं - आईईएलटीएस एकेडेमिक, जो विश्व की टॉप यूनिवर्सटी में दाखिले का रास्ता बनाता है। दूसरा है आईईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग, जो वोकेशनल ट्रेनिंग, प्रवास या नौकरी आदि के लिए होता है। इसकी तारीखें वेबसाइट पर मिल जाएंगी।

कहां से तैयारी की मदद लें

ऑफलाइन : पियर्सन इंस्टीट्यूट, वाई-एक्सिस पीटीई कोचिंग, स्टडी स्मार्ट पीटीई कोचिंग ऑनलाइन अल्फा पीटीई (AlfaPTE), मॉडली ऐप (Mondly App), वाई एक्सिस प्रेप (Y-Axis App). APEUni, सिम्पली इंग्लिश (Simpli English), यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल

अकादमिक योग्यता के टेस्ट कुछ छात्र क्षेत्र विशेष की पढ़ाई करने के लिए विदेशी यूनिवर्सिटी के लिए आवेदन करते हैं। ऐसे में भी अंग्रेजी की योग्यता का आकलन टेस्ट आपको देना होगा। साथ ही एकेडेमिक एफिशिएंसी टेस्ट जैसे जीमैट (मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए). जीआरई (मैनेजमेंट एवं लॉ). सैट (अंडरग्रेजुएट कोर्सेस के लिए). एमसैट (मेडिकल), एलसेट (लॉ) देना होगा। देखें: ieltsidpindia.com टोफिल : टोफिल आईबीटी की मान्यता वेबसाइट के अनुसार 160 देशों की 13000 यूनिवर्सिटीज से अधिक में है। यह 2.5 घंटे का ऑनलाइन टेस्ट होता है। इसे सेंटर पर या घर से दिया जा सकता है। इसका आयोजन एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विसेज (ईटीएस) की ओर से किया जाता है।

देखें: www.ets.org/toefl.html पियरसन टेस्ट ऑफ इंग्लिश अकेडेमिक (पीटीई एकेडेमिक): यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है। दो घंटे की, कंप्यूटर आधारित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)- नहीं आती अंग्रेजी तो क्या करें, आपके मन में बड़ा सवाल ये होगा कि अगर अंग्रेजी नहीं आती तो क्या करें। आपके इस उलझन का जवाब है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। हालांकि, ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आम कोर्स से थोड़ा अलग होते हैं। अब बहुत से ऑनलाइन मंच प्रभावी तरीके से अंग्रेजी सिखा रहे हैं। Alison FutureLearn, Edx, Udemy, Coursera के साथ ही अंग्रेजी सीखने के अन्य प्रमुख मंच हैं: bbc.co.uk/learningenglish. learningenglish.voanews.com. englishonline.britishcouncil.org

स्कॉलरशिप करेंगी मदद

विदेश में पढ़ाई करने की एक अन्य बड़ी बाधा होती है वित्तीय व्यवस्था विदेश में पढ़ना महंगा होता है। ऐसे में आप विदेश में अपने स्टडी काउंसलर से संपर्क कर उससे सलाह ले सकते हैं। छात्र कई स्कॉलरशिप्स का लाभ ले सकते हैं। आपको देखना होगा कि जिस संस्थान में आप आवेदन कर रहे हैं, वहां कितनी तरह की स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि आप लाभ ले सके। इसके बारे में भी जानकारी आपको एजुकेशनल काउंसलर से मिल सकती है।

संचालित परीक्षा के माध्यम से इंग्लिश में आपकी प्रवीणता का आकलन किया जाता है। वैश्विक स्तर पर 3500 से अधिक यूनिवर्सिटी और कॉलेज इंग्लिश लैंग्वेज के मूल्यांकन के लिए पीटीई को मान्यता देते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और कनाडा जैसी सरकारों की ओर से काम, अध्ययन और इमिग्रेशन मकसदों में वीजा आवेदनों के लिए पीटीई स्कोर को स्वीकार करते हैं। देखें: www.pearsonpte.com डुओलिंगो: अंग्रेजी प्रवीणता के लिए यह कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। यह कंप्यूटर एडाप्टव टेस्ट भी है। यानी टेस्ट देने वाले के अनुसार इसके प्रश्नों में बदलाव होता चलता है। टेस्ट लगभग एक घंटे का होता है और अंडरग्रेजुएट, ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए रास्ता बनता है। 5500 से ज्यादा संस्थानों में मान्यता है। देखें: englishtest.duolingo.com कैंब्रिज इंग्लिश एडवांस विश्व में 9000 से ज्यादा शैक्षिक संस्थानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और सरकारी कार्यालयों से मान्यता प्राप्त है। अंग्रेजी भाषा के लिए उच्च स्तरीय टेस्ट है। इसे पहले सीए कहा जाता था, अब सीआई एडवांस के नाम से जाना जाता है। यह चार घंटे का टेस्ट होता है। पढ़ाई, विदेश में नौकरी या प्रवास के लिए यह मान्यता प्राप्त टेस्ट है।

सेल्ट भी है अच्छा विकल्प

करियर काउंसलर आशीष आदर्श मानते हैं कि सेल्ट यानी एसईएलटी (सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट) भी एक बेहतर विकल्प है। इससे लंदन, आयरलैंड, पोलैंड, स्पेन, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड और ऑस्ट्रिया सहित अन्य यूरोपीय देशों में पढ़ाई के लिए जाने का रास्ता खुलता है। यूजी के लिए जाना चाहते हैं, तो सेल्ट का बी-1 स्तर का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बी-2 स्तर का पासिंग स्कोर देना होगा।

विजय गर्ग

अतार्किक दोहन से बिगड़ता जल - चक्र

खाद्य एवं जल विशेषज्ञों के समूह 'ग्लोबल कमीशन आन द इकोनामिक्स आफ वाटर' की ताजा रपट में पाया गया है कि जल संकट से वैश्विक खाद्य उत्पादन का पचास फीसद से अधिक हिस्सा संकट में है। इससे 2050 तक कई देशों के सकल घरेलू उत्पाद में औसतन आठ फीसद की कमी आ सकती है, जबकि कम आय वाले देशों में यह नुकसान 15 फीसद तक हो सकता है। अनुसार, दशकों से हो रहे विनाशकारी भूमि उपयोग और जल कुप्रबंधन ने मानव जनित जलवायु संकट के साथ मिल कर वैश्विक जल- जल चक्र पर गहरा दबाव बना दिया है। यह कई देशों की अर्थव्यवस्था, खाद्य उत्पादन और जन जीवन पर गहरा संकट सकता है। दुनिया भर में करीब तीन अरब लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। एक तरफ फसलें पानी की कमी से मुरझा रही हैं, , तो दूसरी तरफ नगर नगर डूब रहे हैं। अगर इस संकट को नहीं तो परिणाम भयावह होंगे। सुलझाया गया इस त्रासदी को जल खर्च के संतुलित उपयोग से ही नियंत्रित किया जा सकता है। । इसलिए पानी के मोल को पहचानने की जरूरत है। जल चक्र को समझने के लिए इसका वर्गीकरण नीले और हरे पानी में किया गया है। झीलों, नदियों और तालाबों में एकत्रित पानी को नीला पानी कहा जाता है। मिट्टी और पौधों में संचित पानी को हरा पानी कहा जाता है। जल-चक्र उस जटिल प्रणाली को कहते हैं, जिसके द्वारा पानी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पानी भाप बन कर वायुमंडल में जाता है, जिससे जल वाष्प की बड़ी धाराएं बनती हैं, जो ठंडी एवं संघनित होने के बाद बारिश या बर्फ के रूप में धरती पर गिरती हैं। हरे पानी की आपूर्ति को जिस तरह से नजरअंदाज किया जा है, उसे गंभीरता से लेने और सुरक्षित बनाए रखने की जरूरत है। जल चक्र के लिए यह पानी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना नीला पानी माना जाता है, क्योंकि जब ब पौधे जल वाष्प छोड़ते हैं, तो यह वायुमंडल में चला जाता है, इससे धरती पर होने वाली कुल वर्षा का आधा हिस्सा लौट आता है। दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह भी है कि पेड़-पौधों व वनस्पतियों में प्रदूषण अवशोशित करने की क्षमता निरंतर घट रही रही है।

भविष्य में जल चक्र बिगड़ता है, तो भारत में इसका असर कहीं ज्यादा दिखाई देगा। यह स्थिति खाद्य उत्पादन तो घटाएगी ही, पानी की उपलब्धता में भी कमी आ सकती है। दरअसल, हमारी कुछ नीतियां ऐसी हैं, जो जल-चक्र को परिवर्तित कर असंतुलित बना सकती हैं। किसी भी वस्तु में छूट देखने-सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन कृषि के के लिए डीएपी खाद पर दी जा रही सबसिडी पानी और राष्ट्र की सकल पूंजी को हानि पहुंचा रही है। दशकों से किसानों को कृषि विभाग और वैज्ञानिक समझा रहे हैं कि नाइट्रोजन का अधिक प्रयोग खेत में न करें। इससे मिट्टी की उर्वरा क्षमता घटती है और फसलों में पानी भी अधिक लगता है धान, गेहूं, कपास और गन्ना मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर होने पर ज्यादा पानी सोखती हैं। इसीलिए किसानों को मोटा अनाज, दालें व तिलहन पैदा करने और एनपीके खाद डालने को कहा जाता है।

मगर एनपीके पर सबसिडी न होने के कारण यह खाद मंहगी मिलती है। नतीजतन, किसानों ने इसे लगभग खारिज कर दिया है। सरकार डीएपी पर सबसिडी इसलिए दे रही है कि इसे राजनीतिक हानि न उठानी पड़े। यूरिया डीएपी पर प्रतिवर्ष लगभग दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रत्यक्ष सबसिडी दी जाती है। इस कारण धान और गेहूं की फसल ज्यादा उगाई जाती है, क्योंकि ये फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं और इन्हीं का ज्यादा निर्यात होता है। तमाम प्रोत्साहन के बावजूद किसान बहुफसलीय खेती करने से भी कतरा रहे हैं। इस वजह से देश को दलहन और तिलहन बड़ी मात्रा में आयात करने होते हैं। इनके आयात में बड़ी मात्रा में विदेश पूंजी भी खर्च होती है। यही नहीं, गेहूं-चावल की फसलों में जल प्रबंधन और बिजली व्यवस्था में जो धन खर्च होता है, वह भी अप्रत्यक्ष निर्यात के जरिए नुकसान का सबब बन रहा है। मगर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस हकीकत का न तो खुलासा होता है और न ही विपक्ष इन मुद्दों को संसद में उठाता है।

खेती और कृषिजन्य औद्योगिक उत्पादों से जुड़ा यह ऐसा मुद्दा है, जिसकी अनदेखी के चलते पानी का भी निर्यात हो रहा है। इस पानी को 'वर्चुअल वाटर' भी कह सकते हैं। दरअसल, भारत से बड़ी मात्रा में चावल, चीनी, वस्त्र, जूते-चप्पल और फल व सब्जियों का निर्यात होता है। इन्हें तैयार करने में बड़ी मात्रा में पानी खर्च होता है। अब । तो जिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने हमारे यहां बोतलबंद पानी के संयंत्र लगाए हुए हैं, वे भी इस पानी को अरब देशों को निर्यात कर रही हैं। इस तरह से निर्यात किए जा रहे पानी पर लगाम नहीं लगाई गई तो संकट और बढ़ेगा। जबकि देश के तीन चौथाई घरेलू रोजगार पानी पर निर्भर हैं। आमतौर शुद्ध पानी, तेल और लोहे यह भुला दिया मूल्यवान लोहे की तुलना में कहीं क्योंकि पानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में बीस हजार डालर प्रति हेक्टेयर की दर से सर्वाधिक योगदान करता करता है। इस दृष्टि भारत | कृषि और इससे संबंधित उत्पादों के जरिए पानी का जो अप्रत्यक्ष निर्यात हो रहा है, वह हमारे भूतलीय और भूगर्भीय दोनों ही प्रकार के जल भंडारों का दोहन करने को बड़ा सबब बन रहा है। दरअसल, एक टन अनाज उत्पादन में एक हजार टन पानी की आवश्यकता होती है। धान, गेहूं, कपास और गन्ने की खेती में सबसे ज्यादा पानी खर्च होता है। इन्हीं का हम सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं। खेत की मिट्टी और स्थानीय जलवायु भी पानी की कम-ज्यादा खपत से जुड़े अहम पहलू हैं। पानी का अप्रत्यक्ष निर्यात न हो इसके लिए फसल प्रणाली में व्यापक बदलाव और सिंचाई में आधुनिक पद्धतियों को अपनाने की जरूरत है। ऐसा अनुमान है कि धरती पर 1.4 अरब घन किलोमीटर पानी पानी है, , लेकिन इसमें से महज दो फीसद पानी मनुष्य के पीने और सिंचाई के लायक है। इसमें 70 फीसद खेती-किसानी में खर्च होता है। इससे जो फसलें और फल-सब्जियां उपजती हैं, निर्यात के जरिए 15 फीसद पानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में चला जाता है। इस तरह से 1050 अरब वर्गमीटर पानी का अप्रत्यक्ष कारोबार होता है। एक अनुमान के मुताबिक इस वैश्विक कारोबार में लगभग दस हजार करोड़ घनमीटर वार्षिक जल भारत से फसलों के रूप में निर्यात होता है जल के इस अप्रत्यक्ष व्यापार में भारत दुनिया में अव्वल है। जल का संतुलन बना रहें, भविष्य की नीतियां इस दूरदर्शी दृष्टिकोण से बनाना चाहिए।

इंडियन रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन के नए नियम हो गए लागू, यात्रियों के साथ रेलवे को भी होगा फायदा

परिवहन विशेष न्यूज

भारतीय रेलवे ने एडवांस टिकट रिजर्वेशन के नए नियम लागू कर दिया है। नए नियम के अनुसार अब यात्री 60 दिन पहले ही टिकट बुक करवा सकते हैं। अक्टूबर में इसका टेन्योर 120 दिन था। भारतीय रेलवे ने बताया कि नए नियम का लाभ यात्रियों के साथ रेलवे को भी होगा। हम आपको इस आर्टिकल में नए नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे।

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब केवल 60 दिन पहले ही टिकट बुक कर सकते थे। इससे पहले इसका समय 120 दिन यानी चार महीने था। भारतीय रेलवे ने कहा कि इसका लाभ रेलवे के साथ यात्रियों को भी होगा। हम आपको रेलवे के नए नियम (Indian Railway New Rule) के बारे में बताएंगे।

भारतीय रेलवे ने एडवांस रिजर्वेशन नियमों को कई बार बदला है। समय और यात्रियों के हित में रेलवे ने कई बार यह फैसला लिया है। नीचे दी गई इमेज में हमने बताया है कि एडवांस रिजर्वेशन के नियम में कब-कब बदलाव हुआ है।

कम होगी धोखाधड़ी

रेलवे मंत्रालय ने कहा कि कई यात्री 120 दिन पहले टिकट बुक कर लेते हैं पर बाद में इसे कैंसिल करवा लेते हैं। वहीं, कई लोग टिकट ब्लॉक करके धोखाधड़ी भी करते हैं। इन दोनों प्रमुख बातों के कारण रेलवे ने नियम में बदलाव किया है।

रेलवे द्वारा जारी आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पाया जाएगा की 21 फीसदी टिकट कैंसिल हो जाती है और 4 से 5 फीसदी यात्री यात्रा ही नहीं करते है। ऐसे में उन यात्रियों को सीट नहीं मिल पाती है जो उसके अधिकार में हैं। रेलवे ने नए नियम की गाइडलाइन सभी स्टेशन और टिकट काउंटर पर भेज दी है।

रेलवे ने साफ कहा कि जिन यात्रियों ने 120 दिन पहले ट्रेन टिकट बुक किया है, उनपर कोई असर नहीं होगा। वह उस टिकट पर आराम से यात्रा कर सकते हैं। दरअसल, यह नियम 1 नवंबर से लागू हुआ है। 31 अक्टूबर तक एडवांस टिकट बुकिंग का समय 120 दिन ही था।

स्पेशल ट्रेन चलाने में होगी मदद

रेल अधिकारियों ने कहा कि नए नियम के लागू हो जाने के बाद रेलने स्पेशल ट्रेनों की प्लानिंग सही से कर पाएगा। इस नियम से रेलवे यात्रियों की संख्या का सही अनुमान लगा सकता है और फेस्टिव सीजन पर स्टेशन की भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सही संख्या में स्पेशल ट्रेन चला सकते हैं।

विदेशी पर्यटकों पर नहीं पड़ेगा असर

भारतीय रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन नियम विदेशी पर्यटकों पर लागू नहीं होगा। वह 365 दिन पहले एडवांस में टिकट बुक कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने विदेशी पर्यटकों को सहूलियत देने के लिए एडवांस रिजर्वेशन का टेन्योर 1 साल किया।

इतनी बार बदले नियम

साल	एडवांस बुकिंग का समय
अप्रैल 1981 से जनवरी 1985	120 दिन
फरवरी 1985 से अगस्त 1988	90 दिन
सितंबर 1988 से सितंबर 1993	60 दिन
अक्टूबर 1993 से जून 1995	45 दिन
सितंबर 1995 से जनवरी 1998	30 दिन
फरवरी 1998 से फरवरी 2007	60 दिन
मार्च 2007 से जुलाई 2007	90 दिन
जुलाई 2007 से जनवरी 2008	60 दिन
फरवरी 2008 से मार्च 2012	90 दिन
मार्च 2012 से अप्रैल 2013	120 दिन
मई 2013 से मार्च 2015	60 दिन
अप्रैल 2015 से अक्टूबर 2024	120 दिन

6.5 प्रतिशत की वृद्धि के लिए सालाना एक करोड़ नई नौकरियों का करना होगा सृजन- गोल्डमैन सैक्स

रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ( ) की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सालाना 6.5 प्रतिशत की औसत जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) वृद्धि बनाए रखने के लिए सालाना एक करोड़ नौकरियों का सृजन करना होगा। इसके अलावा कपड़ा खाद्य प्रसंस्करण और फर्नीचर जैसे श्रम आधारित सेक्टर को अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन देने से निम्न से मध्यम कौशल वाले श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन में सुविधा होगा।

नई दिल्ली। भारत को सालाना 6.5 प्रतिशत की औसत जीवीए (सकल मूल्य वर्धित) वृद्धि बनाए रखने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 से वित्त वर्ष 2029-30 तक हर साल लगभग एक करोड़ नई नौकरियों का सृजन करना होगा। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, किफायती घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने से रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि यह निर्माण के क्षेत्र में 80 प्रतिशत से अधिक श्रम बल को रोजगार प्रदान करता है।

इसके अलावा यह विभिन्न कौशल स्तरों में रोजगार सृजन को भी महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि टियर-2 और टियर-3 शहरों में आइटी हब और छोटे शहरों में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) स्थापित करने से टियर-1 शहरी केंद्रों पर दबाव कम होगा और कम सेवा वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और फर्नीचर जैसे श्रम आधारित सेक्टर को अधिक राजकोषीय प्रोत्साहन देने से निम्न से मध्यम कौशल वाले श्रमिकों के लिए रोजगार सृजन में सुविधा होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं ने मुख्य रूप से उन उद्योगों को लाभान्वित किया है, जहां पर अधिक पूंजी की जरूरत होती है।

दो दशकों में 19.6 करोड़ नौकरियों का सृजन

रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो दशकों के दौरान भारत में लगभग 19.6 करोड़ नौकरियों का सृजन हुआ है और इनमें से दो-तिहाई पद पिछले एक दशक में सृजित हुए हैं। इस दौरान एक महत्वपूर्ण बदलाव यह हुआ है कि कृषि से निकलकर लोग निर्माण और सर्विस सेक्टर में गए हैं।

भारत में निर्माण रोजगार का प्राथमिक चालक बना हुआ है और कुल रोजगार का 13 प्रतिशत इस क्षेत्र से आता है। रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचे में निवेश ने न केवल नौकरियां पैदा की हैं, बल्कि निम्न-से-मध्यम आय वाले परिवारों में आय के स्तर को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

महीने के पहले शनिवार को भी बंद हैं बैंक, जानें आरबीआई ने क्यों दी छुट्टी

भारतीय रिजर्व बैंक ने नवंबर के लिए बैंक हॉलिडे लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में बैंक हॉलिडे कब और कहां है इसकी जानकारी है।आरबीआई द्वारा जारी बैंक हॉलिडे लिस्ट के अनुसार आज भी देश के कई राज्यों में बैंक की छुट्टी है। इसके अलावा नवंबर में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे।

नई दिल्ली। यह हफ्ता पूरा त्योहारों से भरा हफ्ता है। इस हफ्ते में दीवाली, धनतेरस, दीवाली अमावस्या और भाई दूज जैसे त्योहार मनाए जा रहे हैं। इन त्योहारों के कारण कई राज्यों के बैंक में छुट्टी भी दी गई।

2 नवंबर 2024 (शनिवार) को दीवाली अमावस्या (बलिप्रदा) और गोवर्धन पूजा है। इस अवसर पर कई शहरों के बैंक बंद हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे लिस्ट के अनुसार 2 नवंबर को अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, लखनऊ के बैंकों में छुट्टी है।

नवंबर में कुल कितने दिन बंद रहेंगे बैंक

भारतीय रिजर्व बैंक के हॉलिडे लिस्ट के अनुसार नवंबर महीने में सभी राज्यों का मिलाकर कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। हालांकि, बैंक हॉलिडे होने के बावजूद कस्टमर को बैंक की ऑनलाइन सर्विस, एटीएम और डिजिटल पेमेंट सुचारू रूप से मिलेगी।

इन अवसरों पर बंद रहेंगे बैंक

आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर बैंक हॉलिडे की लिस्ट जारी है। इस लिस्ट में बैंक हॉलिड का दिन, कारण और स्थान की जानकारी दी गई है। नवंबर के महीने में दीवाली अमावस्या (लक्ष्मी पूजन), कुट फेस्टिवल, विक्रम संवत न्यू ईयर, छठ और वांग्ला त्योहार है।

बता दें कि देश के सभी बैंक रविवार और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं।

कब-कब बंद रहेंगे बैंक

2 नवंबर 2024 को बलि प्रतिपदा के मौके पर अहमदाबाद, बेलापुर, बैंगलुरु, देहरादून, गंगटोक, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, लखनऊ के बैंक बंद रहेंगे।

7 नवंबर 2024 को छठ पर्व के अवसर पर कोलकता, पटना, रांची के बैंक में कोई कामकाज नहीं होगा।

8 नवंबर 2024 को छठ पर्व के कारण पटना, रांची, शिलांग के बैंक बंद रहेंगे।

12 नवंबर 2024 को ईगास-बग्वाल के मौके पर देहरादून के सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी।

15 नवंबर 2024 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर अहमदाबाद, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, तेलंगाना, ईटानगर, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोहिमा, कोलकता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, रायपुर, रांची, श्रीनगर, शिमला के बैंक बंद रहेंगे।

18 नवंबर 2024 को कनकदास के कारण बैंगलुरु के बैंकों में छुट्टी रहेगी।

23 नवंबर 2024 को Seng Kutsnem के मौके पर शिलांग के बैंक बंद रहेंगे।

कौन तय करता है बैंक हॉलिडे

देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ही सभी राज्यों के लिए बैंक हॉलिडे लिस्ट तैयार करता है। यह लिस्ट राज्य त्योहार, नेशनल हॉलिडे आदि को देखते हुए बनाया जाता है। अगर बैंक हॉलिडे लिस्ट के अलावा किसी और दिन बैंकों का अवकाश होता है तो आरबीआई इसके लिए अलग से सर्कुलर या नोटिफिकेशन जारी करता है।

शानदार रिटर्न के लिए कर सकते हैं टैक्स फ्री सरकारी बॉन्ड में निवेश, इन्वेस्टमेंट से पहले कुछ बातों का रखें ध्यान

अगर आप शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं और सिक्योर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। वैसे को स्टॉक मार्केट में स्टॉक गोल्ड ईटीएफ के अलावा भी कई ऑप्शन है। आप टैक्स-फ्री बॉन्ड ( ) में निवेश कर सकते हैं। इसमें मिलने वाले रिटर्न पर आपको टैक्स का भुगतान भी नहीं करना होगा और साथ यह सिक्योर ऑप्शन भी है।

नई दिल्ली। आज के समय में इन्वेस्टमेंट के कई ऑप्शन मौजूद हैं। लेकिन, कुछ समय से बाजार में बॉन्ड ने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन्टरेस्ट रेट घटाने की उम्मीद के बाद टैक्स-फ्री बॉन्ड्स ने चमक उठा है।

निवेशक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर से टैक्स-फ्री बॉन्ड्स में निवेश कर सकते हैं। वर्तमान में स्टॉक मार्केट कुछ टैक्स-फ्री बॉन्ड्स अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। इन बॉन्ड्स का यील्ड भी काफ अट्रैक्टिव है। इसके अलावा यह सिक्योर और रेगुलर इनकम वाले बॉन्ड हैं।

यह बॉन्ड उन निवेशकों के लिए काफी अच्छा है जो ज्यादा टैक्स स्लैब (Tax Slab) में शामिल हैं।

इन कंपनियों के बॉन्ड्स में कर सकते हैं निवेश

बाजार की टोटल 14 इन्फ्रास्ट्रक्चर सरकारी कंपनी (जैसे-NHAI, IRFC और Power Finance Corporation (PFC) आदि) ने टैक्स-फ्री बॉन्ड्स जारी किए। इन बॉन्ड्स की ट्रेडिंग मुख्य स्टॉक एक्सचेंज पर होती है।

आपको बता दें कि यह बॉन्ड्स साल 2012 और 2016 के बीच जारी हुआ। इसे 10 साल, 15 साल और 20 साल के लिए जारी किया गया। खास बात यह है कि इस बॉन्ड पर मिलने वाला इंटरेस्ट का भुगतान हर साल में हो जाता है। इन सभी बॉन्ड में से लगभग सभी बॉन्ड को 'AAA' की रेटिंग मिली है।

क्यों फायदेमंद है ये बॉन्ड

टैक्स-फ्री बॉन्ड निवेश के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। दरअसल, इससे होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा यह बॉन्ड सरकारी कंपनियों द्वारा जारी किया जाता है, इस वजह से यह पूरी तरह से सिक्योर है। यह बॉन्ड उन निवेशकों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है जो अपनी सेविंग को सिक्योर के साथ उससे रेगुल इनकम कमाना चाहते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप क्स-फ्री बॉन्ड्स में निवेश करने का सोच रहे हैं तो आपको कंपनी के लिक्विडिटी और यील्ड टू मैच्योरिटी (YTM) का ध्यान रखना चाहिए। YTM का मतलब बॉन्ड का सालाना रिटर्न है। आपको इन बॉन्ड में मैच्योरिटी तक निवेश करना चाहिए।

लोग धड़ाधड़ कर रहे यूपीआई, अक्टूबर में लेनदेन का आंकड़ा 23.5 लाख करोड़ रुपये पार

यूपीआई ने ऑनलाइन पेमेंट को काफी आसान कर दिया है। हर महीने यूपीआई एक नया रिकॉर्ड दर्ज करता है। पिछले महीने अक्टूबर में भी यूपीआई के नाम एक नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। साल 2016 में यूपीआई के चालू होने के बाद से एक महीने में सबसे अधिक संख्या में यूपीआई ट्रांजैक्शन हुआ है। आइए इस रिपोर्ट में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। यूपीआई आधारित डिजिटल लेनदेन में वृद्धि जारी है। अक्टूबर महीने में यूपीआई से देश में 23.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के 16.58 अरब लेन-देन हुए। यह अप्रैल 2016 में यूपीआई के चालू होने के बाद से एक महीने में सबसे अधिक संख्या है।

शुक्रवार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, सितंबर की तुलना में अक्टूबर में मात्रा में 10 प्रतिशत और मूल्य में 14 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। अक्टूबर में दैनिक यूपीआई लेनदेन मात्रा के हिसाब से 53.5 करोड़ और मूल्य के हिसाब से 75,801 करोड़ रुपये को पार कर गया, जबकि सितंबर में यह 50.1 करोड़ रुपये और 68,800 करोड़ रुपये था।

अक्टूबर में 46.7 करोड़ इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपीएस) लेनदेन हुए, जो सितंबर में 43 करोड़ से नौ प्रतिशत अधिक हैं। मूल्य के हिसाब से, आईएमपीएस लेनदेन सितंबर के 5.65 लाख करोड़ रुपये की तुलना में 11 प्रतिशत बढ़कर 6.29 लाख करोड़ रुपये हो गए।

फास्टैग लेनदेन की संख्या सितंबर के 31.8 करोड़ की तुलना में अक्टूबर में आठ प्रतिशत बढ़कर 34.5 करोड़ हो गई। अक्टूबर में 6,115 करोड़ रुपये के लेनदेन हुए, जो सितंबर में 5,620 करोड़ रुपये थे। अक्टूबर में आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (एईपीएस) पर 12.6 करोड़ लेनदेन हुए जो सितंबर के 10 करोड़ से 26 प्रतिशत अधिक है। डिजिटल भुगतान की हिस्सेदारी मार्च, 2021 के 14-19 प्रतिशत से दोगुनी होकर मार्च, 2024 में 40-48 प्रतिशत हो गई।

इसमें यूपीआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। यूपीआई आधारित लेनदेन की मात्र इस साल की पहली छमाही में 52 प्रतिशत बढ़कर 78.97 अरब हो गई जो पिछले साल की समान अवधि में 51.9 अरब थी। इसी तरह लेनदेन का मूल्य इस साल के पहले छह महीनों में 40 प्रतिशत बढ़कर 83.16 लाख करोड़ रुपये से 116.63 लाख करोड़ रुपये हो गया।

भारतीय नदी परिषद अध्यक्ष रमन कांत ने बताई यमुना की 3 समस्याएं, पानी की कमी; प्रदूषण और अतिक्रमण

यमुना नदी की दुर्दशा पर चिंता जताते हुए भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष रमन कांत ने नदी की तीन प्रमुख समस्याओं – पानी की कमी प्रदूषण और अतिक्रमण पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने यमुना को पुनर्जीवित करने के लिए सामूहिक प्रयासों और वैज्ञानिक समाधानों पर बल दिया। यमुना की सफाई से दिल्ली के वायु प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। नदियां किसी भी शहर की जीवन रेखा होती हैं, लेकिन इसे देश की राजधानी का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि यहां की जीवन रेखा खुद ही डायलिसिस पर है। ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाली यमुना नदी खुद अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है।

इसके जल का आचमन करना तो दूर की बात, दिल्ली में यमुना कहीं स्नान करने लायक भी नहीं है। हालांकि राजनीतिक दलों के एजेंडे में यमुना की सफाई प्राथमिकता पर होती है, लेकिन हर बार कागजों- भाषणों तक ही सिमट जाती है। आखिर कैसे मिले इस पवित्र नदी को पुनर्जीवन?

इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे हुए हैं भारतीय नदी परिषद के अध्यक्ष रमन कांत। गंगा-यमुना दोआब में मेरठ जनपद के पूठी गांव में जन्मे रमन कांत वर्ष 2001 से ही नदी पुनर्जीवन के कार्य में लगे हैं। उन्होंने हिंडन, काली, नीम और करवन जैसी दर्जनों नदियों के तकनीकी अध्ययन किए हैं तथा उनके उद्गम खोजे हैं।

नीम नदी उद्गम पुनर्जीवन के कार्य को प्रधानमंत्री द्वारा अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी शामिल किया गया था। रमन लगातार देश की छोटी नदियों को जानने-समझने, विलुप्त नदियों को खोजने तथा नदियों को पुनर्जीवित करने के कार्य में लगे हैं।

रमन ने देश में नदियों के पुनर्जीवन के कार्य को सामूहिक रूप से आगे बढ़ाने के लिए 'भारतीय नदी परिषद' का गठन किया। भारतीय नदी परिषद के माध्यम से 'उत्तर प्रदेश का नदी नीति प्रारूप' विकसित कर उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा है। नदी पुनर्जीवन कार्यों के लिए इन्हें भारत सरकार का राष्ट्रीय जल पुरस्कार तथा अमेरिका का प्रतिष्ठित 'टैरी बेकर' पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। वह 'रिवरमैन आफ इंडिया' के नाम से भी ख्यात हैं।

संवाददाता ने उनसे यमुना नदी की दुर्दशा और पुनर्जीवन की संभावना पर विस्तार से बातचीत की। उनका कहना है कि यमुना नदी की तीन बड़ी समस्याएं हैं...पानी की कमी, प्रदूषण और अतिक्रमण। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंशः

यमुना नदी दिल्ली में गंदे नाले में बदल चुकी हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है?

अगर बरसात के कुछ दिनों को छोड़ दें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि यमुना इस समय गंदे नाले में ही तब्दील हो चुकी है। नदी के पानी में कोई जीवन नहीं बचा है। वर्तमान में यमुना केवल घरेलू बहिस्राव लेकर बहने वाली एक धारा बन चुकी है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यमुना नदी इस समय बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। इस सब के पीछे सीधे तौर पर हम सभी कसूरवार हैं। हम सब इसलिए क्योंकि वो लोग हम में से ही हैं जो यमुना के प्रदूषण का कारण हैं और वो भी हम ही हैं, जो कि यह सब होते देख रहे हैं।

यमुना को स्वच्छ बनाने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार बार-बार प्रतिबद्धता जताती रही हैं, लेकिन स्थिति नहीं बदलती, बाधा क्या है?

किसी बात के समाधान के विषय में कह देना और कही हुई बात को अमल करना दोनों अलग विषय हैं। हमें यह देखना चाहिए कि जो प्रतिबद्धता जताई गई है उसमें गंभीरता कितनी है। क्योंकि अगर हम वास्तव में किसी समस्या को लेकर गंभीर हैं तो कोई कारण नहीं कि उस समस्या का समाधान न हो सके। राजनीति में कुछ बातें कहने के लिए कह दी जाती हैं, लेकिन उन विषयों को प्राथमिकता पर नहीं रखा जाता है। जिस दिन यमुना नदी के विषय को गंभीरता से लेकर प्राथमिकता पर लिया जाएगा उस दिन से समाधान की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ेगा। बाक़ी तो बातें हैं बातों का क्या।

यमुना नदी की सफाई के लिए क्या कार्ययोजना होनी चाहिए?

पानी की कमी, प्रदूषण और अतिक्रमण ये तीन प्रमुख यमुना नदी की समस्याएं हैं। तीनों समस्याओं के पीछे अलग-अलग कारण हैं। इन कारकों को समझ कर उनके लिए शीघ्र एवं दूरगामी दोनों प्रकार की योजनाओं को बनाकर उनको अमल में लाना होगा। इसमें विषय विशेषज्ञों व समाज की भागीदारी आवश्यक है। सरकारी तंत्र में मन के हारे हुए, निराश व नकारात्मक लोगों को इस काम से दूर रखना होगा।

यमुना नदी सबसे अधिक प्रदूषित कहां और क्यों होती हैं? इसमें दिल्ली की कितनी भागीदारी है?

यमुना नदी में पानी की कमी लगातार गंभीर चिंता पैदा कर रही है। यमुना जब दिल्ली की सीमा में प्रवेश करती है तो इसमें पानी की मात्रा बहुत कम हो जाती है। यहां से आगे दिल्ली की लगभग दो करोड़ आबादी का मलमूत्र इसमें मिलता है जो कि यमुना नदी को एक गंदे नाले में बदल देता है। दिल्ली के अंदर यमुना में जो प्रदूषण दिखता है वह सब दिल्ली वालों का है और दिल्ली वाले ही दिल्ली में यमुना को प्रदूषित करने के लिए कसूरवार भी हैं। ऐसा नहीं है कि दुनिया के और देशों में इतनी बड़ी मात्रा में घरेलू कचरा नहीं निकलता है, लेकिन वे उसको बेहतर तरीके से शोधित करके अपनी नदियों में डालते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं यहां भी हैं, लेकिन उनका संचालन व्यवस्थित नहीं है। यही वजह है कि यमुना दिन ब दिन प्रदूषित होती जा रही है।

यमुना को साफ करने से ज्यादा जरूरी उसमें गंदगी गिरने से रोकना है। आप इसे किस तरह से देखते हैं?

हम सभी ने देखा है कि कोविड के दौरान देश की नदियों का अलग ही स्वरूप निखर कर आया। तमाम नदियों की निर्मलता लौटने लगी। यह सब देखकर पूरा देश हतप्रभ था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नदियों के पास मानव का दखल कम हुआ। बस यही सूत्र है, हम अगर अपनी यमुना की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसको बिगाड़ने से बचें। हमें यमुना के जीवन में अपना कम करना होगा। नदी के संभरण क्षेत्र में जीतने भी प्रतिष्ठान हैं उनको अपना आंकलन करना चाहिए कि उनका तरल व ठोस कचरा कहां जाता है।

यमुना नदी स्वच्छ होने से दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने में कितनी मदद मिलेगी?

इसका सर्वाधिक उपयुक्त जवाब यमुना किनारे बसे लोगों से पूछना चाहिए। यमुना नदी किनारे के घरों में लगे बिजली से चलने वाले उपकरण अधिक नहीं चल पाते हैं। यमुना से उठने वाली बदबू लोगों की सांसों को दूषित कर रही है जिस कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी होती हैं। यमुना नदी से उठने वाली बदबू से यमुना ही नहीं, उसके आस-पास भी प्रदूषित माहौल बन जाता है।

यमुना की यह दुर्दशा क्या दिल्ली के पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही है?

किसी भी नदी की अपनी प्रकृति होती है। नदी के इस व्यवहार को समझना होगा। कोई भी नदी केवल एक धारा नहीं होती है। नदी का अपना एक आभामंडल भी होता है जिसको संभरण क्षेत्र या बेसिन कहते हैं। अगर नदी के संभरण क्षेत्र को ही कब्जा लिया जाएगा तो नदी बहुत दिन तक जीवित नहीं बनी रहती है। नदी बरसात में अपने संभरण क्षेत्र व भूजल को समृद्ध करती है और बरसात के बाद वही भूजल व उसका संभरण क्षेत्र नदी की धारा को समृद्ध करता है। ऐसे में जब नदी के संभरण क्षेत्र को कब्जा करके उसको नहर बन दिया जाएगा तो नदी की प्रकृति ही नष्ट जो जाएगी। दिल्ली में यमुना नदी के साथ यही हो रहा है। नदी की स्मृति बहुत तेज होती है, जब विगत वर्ष बरसात के दौरान यमुना का पानी लाल किले से मिलकर बह रहा था तो यमुना ने बता दिया कि मेरी हद यहां तक है।

यमुना की इस दुर्दशा से दिल्लीवासियों का जनजीवन कैसे प्रभावित हो रहा है?

जब दिल्ली बसी थी तो यमुना नदी उसकी शान थी। वह यमुना नदी ही थी जोकि यहां के वसियों की पानी की सभी जरूरतें पूरा करती थी। कभी इस यमुना किनारे ही समृद्ध पर्यटन था। मजनूं का टीला हो या नदी किनारे के अखाड़े सब यमुना से ही सौंदर्य पाते थे। वर्तमान में यमुना नदी के हालात देखकर कोई भी दिल्लीवासी नहीं चाहता है कि वो इसके किनारे भ्रमण करे। नदी पूरी जैवविविधता होती है। दिल्ली के अंदर यमुना में कोई जीवन नहीं है। जिस नदी के किनारे सुकून व आनंद मिलता था, आज उस नदी किनारे कोई खड़ा होने को तैयार नहीं है।

इस नदी की सफाई पर शायद हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन हाल बद से बदतर ही हुए हैं। क्यों?

जब हम किसी भी काम को केवल तुरंत प्रभाव के लिए करेंगे तो जाहिर है कि उसका असर भी कुछ समय के लिया ही होगा। इसका एक आंकलन तो होना चाहिए कि यमुना नदी सुधार हेतु जिस-जिस कार्य में पैसा खर्च हुआ उन कार्यों को जिनके कहने पर किया गया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे लोग अभी भी ग़लत सलाह सरकार को दे रहे हों। दूसरा पहलू यह है कि यमुना नदी सुधार के कार्य को अगर स्थायी बनाना है तो उसमें जहां समाज की भूमिका सुनिश्चित करनी होगी वहीं समाधानों के लिए केवल वैज्ञानिक तरीके पर भी निर्भरता घटानी होगी। जब सीवरेज शोधन के लिए बनाए जाने वाले शोधन संयंत्र पूरी तरह से कामयाब नहीं हैं और उन पर खर्च भी अधिक हो रहा है तो ऐसे में इस कार्य को विकेंद्रित तरीके से करने तथा शोधन के इन सी टू वेटलैंड जैसे प्राकृतिक विकल्प तलाशने होंगे।

इन सी टू वेटलैंड क्या है?

जी हां, यह प्रयोग सफल रहा है। इन सी टू वेटलैंड नदी व नालों के अंदर बनाया जाता है। यह पानी को साफ करने का पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका है। इस पद्धति में नदी के अंदर 500 मीटर या एक किलोमीटर का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें पांच से छह ब्लाक बनाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक का काम अलग-अलग होता है। पहले ठोस कचरे को रोकना। फिर गाद को स्टेनलेस करना और प्राकृतिक तरीके से पानी को कुछ खास पौधों की जड़ों से बहाना। अंत में पानी साफ होकर बाहर निकलता है।

एक इन सी टू वेटलैंड को बनाने की लागत करीब चार से पांच करोड़ रुपये है। नमामि गंगे द्वारा हमारी पहल पर गंगा की सहायक पूर्वी काली नदी में इसका परीक्षण भी किया जा रहा है। नामामि गंगे द्वारा यह काम उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया है। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध वनस्पतिशास्त्री डा सी आर बाबू की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह भविष्य की तकनीक है।

क्या यमुना की सफाई में तकनीकी और प्रशासनिक अड़चनें भी हैं?

जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब कोई तकनीक किसी भी कारण से कामयाब नहीं हो रही है तो ऐसे में या तो उन कारणों को खोजकर उनका समाधान किया जाए या फिर दूसरे विकल्पों की तरफ़ मुडना चाहिए। जहां तक प्रशासनिक अड़चनों की बात है तो हमें किसी एक विभाग को संपूर्ण जिम्मेदारी देकर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। इस कार्य में कई विभागों की संलिप्तता से अवश्य कार्य पर असर होता है। एक सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब से प्रदूषण नियंत्रण विभाग बना है तब से नदियों में प्रदूषण घटने के बजाय बढ़ा है। प्रदूषण नियंत्रण विभाग पंगु क्यों है, इसके लिए या तो उसको अधिक शक्तियां दी जाएं या फिर उसका विकल्प तलाशा जाना चाहिए।

आपके हिसाब से यमुना को इसके मूल रूप में वापस लाने का कारगर और व्यवहारिक उपाय क्या है?

सबसे पहले नदी से जुड़े सभी हितधारकों को प्रभावशाली व्यक्ति साथ बैठाया जाए तथा सभी से विफलता के कारणों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा। इसके बाद एक-एक समस्या के वैज्ञानिक व प्राकृतिक तरीकों के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए विचार कर अंतिम निर्णय लिया जाना चाहिए। जब योजनाओं को जमीन पर उतारना हो तब समाज की भी भूमिका उसमें तय होनी चाहिए। यमुना नदी के सुधार का कार्य कठिन है, लेकिन नामुमकिन कतई नहीं। ऐसे सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए ही हमने भारतीय नदी परिषद का गठन किया है। इसके माध्यम से हम नदी पुनर्जीवन के संकल्प आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा लक्ष्य भारत सरकार के जल विजन 2048 में अपनी भूमिका तय करते हुए भारत की नदियों को निर्मल व अविरल बनाना है।

केरल एक्सप्रेस की चपेट में आने से चार कर्मचारियों की मौत, ट्रैक की सफाई करते समय हुआ हादसा

केरल के पलक्कड़ में चार सफाई कर्मचारियों की केरल एक्स्प्रेस की चपेट में आने से मौत हो गई है। हादसा तब हुआ जब कर्मचारी ट्रैक की सफाई कर रहे थे। तभी वहां से गुजर रही केरल एक्स्प्रेस से इनकी टक्कर हो गई। मौके पर ही दो महिला समेत चार कर्मचारियों की मौत हो गई। इनमें से तीन के शव बरामद कर लिए गए हैं।

पलक्कड़। नई दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली केरल एक्स्प्रेस की चपेट में आने से चार सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रेलवे पुलिस ने के हवाले से बताया कि हादसा शनिवार शाम को शोरानूर रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जहां केरल एक्सप्रेस से टकराने के बाद तमिलनाडु की दो महिलाओं समेत चार सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई।

पीटीआई के अनुसार ट्रेन ने दोपहर करीब 3.05 बजे इन कर्मचारियों को टक्कर मार दी, जब ये कर्मचारी रेलवे स्टेशन से कुछ किलोमीटर दूर शोरानूर पुल के पास रेलवे ट्रैक से कचरा साफ कर रहे थे। रेलवे द्वारा सफाई कार्य के लिए नियुक्त कर्मचारी टक्कर के कारण ट्रैक से नीचे गिर गए।

तीन शव बरामद

पुलिस ने एजेंसी को बताया कि इलाके से तीन शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि चौथे शव का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके भारतपुझा नदी में गिरने का संदेह है। हादसे की सूचना मिलने के बाद रेलवे पुलिस की एक टीम भी मौके पर पहुंची।

शोरानूर रेलवे पुलिस के एक अधिकारी ने एजेंसी को बताया, 'हो सकता है कि कर्मचारियों ने ट्रेन को आते हुए नहीं देखा हो, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई, लेकिन आगे की जांच जारी है।'

तमिलनाडु के रहने वाले हैं मृतक

समाचार एजेंसी आईएएनएस के अनुसार सभी मृतक तमिलनाडु के सलेम के रहने वाले हैं। दोनों पुरुष सफाई कर्मचारियों का नाम लक्ष्मण था, जबकि महिलाओं की पहचान वल्ली और रानी के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, जब यह दुर्घटना हुई, ये कर्मचारी भारतपुझा नदी के ऊपर कोच्चि पुल पर रेलवे ट्रैक पर कूड़ा उठा रहे थे। तभी तेजी से आ रही केरल एक्सप्रेस ट्रेन को देखकर ये असहाय कर्मचारी छिप नहीं पाए और चारों की तुरंत मौत हो गई।

ये कर्मचारी एक रेलवे ठेकेदार से जुड़े हुए हैं, जिसने क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सफाई का काम लिया था। रिपोर्टों के अनुसार, इन श्रमिकों को यह एहसास नहीं हुआ कि केरल एक्सप्रेस पुल से गुजरने वाली है, जब वे उस पर चल रहे थे।

861 करोड़ की लागत से सड़कों के गड्ढे भरेंगे चंद्रबाबू नायडू, CM ने खुद सड़क की मरम्मत कर अभियान शुरू किया

चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की सड़कों को बेहरतर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। सीएम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। अनकापल्ली जिले के चिंतलागोर्लिवनिपालम गांव से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद एक गड्ढे को मोर्टार से भरकर उसकी मरम्मत की। सड़कों की समस्या को देखते हुए अभियान शुरू किया गया है।

अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की सड़कों को बेहरतर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया। सीएम ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। 861 करोड़ रुपये की लागत के इस अभियान को सड़कों की समस्या को देखते हुए शुरू किया गया है। अनकापल्ली जिले के चिंतलागोर्लिवनिपालम गांव से राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने खुद एक गड्ढे को मोर्टार से भरकर उसकी मरम्मत की।

ओड़शिा की आदिबासी इलाका दरिंगीबाड़ी में आम टकुआ ने दो लोगों की जान ले ली

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़शिा

भुबनेश्वर : आम टाकुआ ने ओड़शिा के सिर पर फिर से लांछन लगाया। कंधमाल दरिंगाबाड़ी में टाकुआ खाने से 2 लोगों की मौत, 7 मरीजों का अस्पताल में इलाज। सरकार ने कहा की आहार से इनकार पिछली प्रथा के कारण था।आम टकुआ के खीरी ने दो लोगों की जान ले ली है। 7 महिलाएं अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर मौत से जूझ रही हैं। आम का पेस्ट खाने से 2 दिन से भी कम समय में गांव की महिला बीमार पड़ गई। लड़ाई में रमिता और रुनु की जान चली गई, हालांकि बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिससे पूरा मंदीपंका शोक में डूब गया है। इस घटना ने न सिर्फ 2 लोगों की जान ले ली है , बल्कि एक बार फिर ओडिशा पर कलंक लगा दिया है। इससे पहले काशीपुर का आम टकुआ जौ अघाटन ओडिशा के लिए एक अभिशप्त अध्याय रच चुका है। इसके बावजूद काशीपुरवासियों को आम टकुआ से निजात नहीं मिल पाई है। सवाल उठता है, सरकार से मासिक राशन तो मिल रहा है, लेकिन भोजन की थाली में आम टकुआ की जगह कैसे हो गयी? कौन कहता है कि पहले वाले खा गए, हम खा

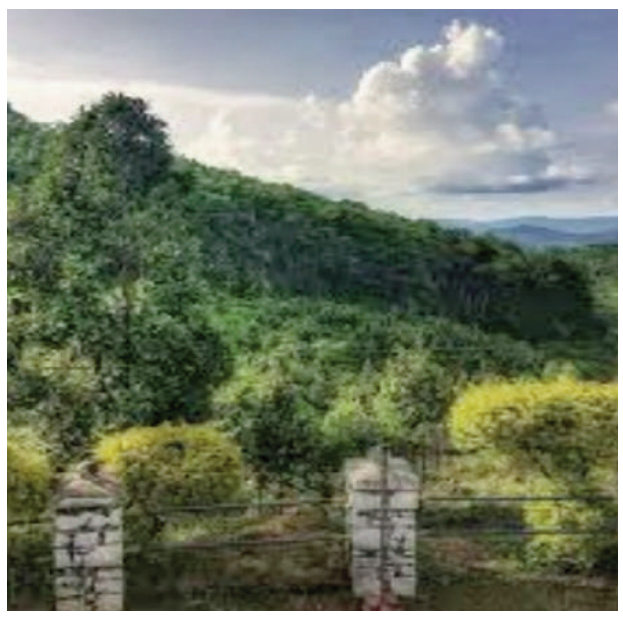

रहे हैं और कौन कहता है कि सरकार का मुफ्त चावल कमी दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं है।उधर, सरकार ने साफ किया है कि ऐसी स्थिति कमी की वजह से नहीं बल्कि पहले की परिपाटी की वजह से बनी है। 2001 में काशीपुर में आम टकुआ पेज ने 32 लोगों की जान ले ली। इस घटना की पूरे ओडिशा में निंदा हुई। अब मंडीपंका में आम की जान लेने की सरकार की क्षमता पर सवालिया निशान लग गया है। यह सच है कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकना है। क्योंकि उपनगर के आदिवासी इलाकों में अभी भी सरकारी योजना उपलब्ध नहीं है।

बचपन और पटाखों की आस

एक बार फिर याद आई, बचपन की वह दिवाली।
जो होती थी बहुत खास, पटाखों की रहती आस।
वह तीन-चार बच्चे, जो होते थे दिल के बड़े सच्चे।
नहीं होता था पास पैसा, दिन गुजरता ऐसा-वैसा।
तब भर जाती थी सड़के, पटाखों की कचरापट्टी से।

एक बार फिर याद आई, बचपन की वह दिवाली।
जो होती थी बहुत खास, पटाखों की रहती आस।
जहां बड़े घर का कोई भी व्यक्ति लंबी लड़ लगाता।
कुछ फूटते-कुछ छूटते तो अपना फायदा कर जाता।
कोई बम मिलता तो हमारा चेहरा खिल-खिल जाता।

एक बार फिर याद आई, बचपन की वह दिवाली।
जो होती थी बहुत खास, पटाखों की रहती आस।
हम एक-दूजे को गले लगाते दिल भी खुश हो जाता।
कुछ समय के लिए गरीबी का दुख क़ाफूर हो जाता।
मिठाई खाने का दर्द सीने में कहीं दबकर रह जाता।
यारों खील-बताशे और धानी से ही काम चल जाता।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, सूत्रधार व समीक्षक)

सकीर्तन कर लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा; 6 मरे, 5 घायल

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़शिा

सुदरगड/भुबनेस्वर् : ओड़शिा की सुंदरगड जिले हेमगिरी पुलिस स्टेशन गाइकनपल्ली के पास बड़ा हादसा। टाटा मैजिक को ट्रेलर के पीछे से टक्कर मार दी गई। 6 मरे, 5 घायल। कीर्तन कर लौटते समय यह हादसा हुआ । गांव के यहां टीम एक व्यक्ति के घर संकीर्तन के लिए गई। जब वह लौट रहा था तो रात करीब ढाई बजे गायकनापाली रोड के किनारे कोयला लदा एक ट्रॉलर खड़ा था। संतुलन बिगड़ने से टाटा मैजिक ट्रेलर के पिछले हिस्से से टकरा गई। परिणामस्वरूप, 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। मालूम हो कि मृतक कंडागोड़ा गांव और समरपिंडा गांव के रहने वाले थे।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023